दिल्ली (राजधानी) गाजियाबाद (उ.प्र.) एवं देहरादून (उत्तराखंड) से एक साथ प्रकाशित

@manasvi_vani

www. manasvivani.com

मनस्वी वाणी

केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त

राष्ट्रवादी विचारधारा को समर्पित दैनिक समाचार पत्र

आपका विश्वास हमारी पहचान

वर्ष : 3 ॥ अंक : 92 ॥ नई दिल्ली, सोमवार, 2 मार्च 2026 RNI.NO.DELHIN/2023/90791 : manasvivani@gmail.com 8285002838

अमेरिकी इजरायली हमलों में ईरान के सुप्रीम नेता खामेनेई की मौत, राष्ट्रपति सहित तीन लोगों की परिषद ने संभाली बागडोर

तेहरान/वाशिंगटन। ईरान की राजधानी तेहरान पर शनिवार तड़के हुए अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई (86) की मौत हो गयी। उनके अलावा ईरान के कुछ और शीर्ष अधिकारी भी मारे गये हैं। वहीं दूसरी तरफ रविवार को इजरायली वायुसेना ने तेहरान पर फिर से नये हमले शुरू किये हैं।

ईरान ने सैन्य बलों के चार वरिष्ठ कमांडरों के मारे जाने की पुष्टि की है। इनमें सैन्य बलों के प्रमुख अब्दुलरहीम मौसवीं और ईरान के रक्षा मंत्री एवं पूर्व वायुसेना कमांडर अजीज नसीरजादेह, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) कमांडर मोहम्मद पाकपुर, और श्री खामेनेई के सुरक्षा सलाहकार एवं रक्षा परिषद के सचिव अली शमखानी शामिल हैं। खामेनेई के निधन के बाद देश की बागडोर एक तीन सदस्यीय समिति को सौंप दी गयी। इसमें राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई और कानून विद अलीरेजा अराफी शामिल हैं। उनके अलावा शीर्ष सैन्य अधिकारी अहमद वाहिदी को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) का नया कमांडर नियुक्त किया है। उन्होंने अमेरिका-इजरायल हमले में मारे गए श्री मोहम्मद पाकपोर का स्थान लिया है। ईरान में श्री खामेनेई की मौत के बाद 40 दिन की शोक अवधि का ऐलान किया गया है। श्री खामेनेई की बेटी, दामाद और नाती भी हमलों में मारे गयी। फ़ार्स समाचार एजेंसी ने कहा, 'सर्वोच्च नेता के घर में जानकार सूत्रों से संपर्क स्थापित करने के बाद,उनकी बेटी, दामाद और नाती की मौत की खबर की दुर्भाग्यवश पुष्टि हो गयी है।' यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि श्री खामेनेई की तीन बेटियों में से कौन मृतकों में शामिल है। फ़ार्स न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि राजधानी पर हुए हमलों के दौरान श्री खामेनेई 'अपने घर में मौजूद कार्यालय में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शहीद हुए।' बाद में सरकारी टेलीविजन ने उनकी मृत्यु की पुष्टि की। ईरान सरकार ने इस हत्या को 'एक बड़ा अपराध' बताया, जो 'इस्लामी दुनिया के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा। ' अमेरिकी मीडिया ने इजरायली सूत्रों का हवाला देते हुए कहा है कि शनिवार के हमलों 40 ईरानी अधिकारियों की मौत हुई है, हालांकि ईरान की ओर से ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गयी। इजरायली रक्षा बल (आइडीएफ) ने रविवार को ताजा हवाई हमले की जानकारी देते हुए एक बयान में कहा, 'ऑपरेशन 'रोरिंग लायन' शुरू होने के बाद पहली बार आइडीएफ, तेहरान के शासकीय केंद्रो पर हमला कर रहा है। वहीं, तेहरान से मिली खबरों के मुताबिक, रविवार सुबह शहर के कई इलाकों में धमाके हुए। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गयी तस्वीरों में तेहरान के कई हिस्सों से घने धुएं के बड़े गुबार उठते देखे गये। पेजेशकियान ने श्री खामेनेई की हत्या का बदला लेने का संकल्प लेते हुए चेतावनी दी कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को 'पछताना पड़ेगा'।

दिल्ली पुलिस का साइबर ठगों पर बड़ा एक्शन: 11 राज्यों में छापेमारी

■ डेढ़ करोड़ की ठगी का खुलासा: 27 आरोपी पकड़े

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम जिला साइबर सेल ने जालसाजों के खिलाफ देशव्यापी कार्रवाई करते हुए 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सप्ताहभर चले इस विशेष अभियान में 11 राज्यों में एक साथ छापेमारी की और पुलिस ने करीब 10 बड़े मामलों का खुलासा किया है। इन मामलों में डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक की ठगी सामने आई है, जबकि आरोपियों के बैंक खातों में करीब 13.91 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन का पता चला है। जिला पुलिस उपायुक्त दरादे शरद भास्कर ने बताया कि साइबर सेल की टीम ठगी के मामलों की जांच कर रही थी। तकनीकी जांच करने के बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और फिर जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों में एक साथ दबिश दी।गिरफ्तार आरोपियों का संबंध निवेश ठगी, एपीके फाइल ठगी, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए ठगी, क्रेडिट कार्ड जालसाजी सहित अन्य ठगी से है।

खामेनेई के मारे जाने पर ईरानी राष्ट्रपति का बड़ा ऐलान

मुसलमानों के खिलाफ खुली जंग

नई दिल्ली। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि खामेनेई की हत्या अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों में हुई है। उन्होंने इस घटना को मुसलमानों के खिलाफ खुली जंग की घोषणा करार दिया, खासकर शिया समुदाय के लिए। राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति और विश्व स्तर पर शिया नेतृत्व के प्रमुख व्यक्तित्व की हत्या पूरी दुनिया में मुसलमानों, विशेष रूप से शियाओं के खिलाफ युद्ध की शुरुआत मानी जा रही है। यह बयान ईरानी राज्य टीवी पर प्रसारित किया गया। खामेनेई की मौत ने ईरान में गहरा सदमा पैदा किया है और देश में 40 दिनों का शोक मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने आगे कहा कि इस ऐतिहासिक अपराध के कर्ताधर्ताओं और साजिशकर्ताओं से बदला लेना इस्लामी गणराज्य ईरान का वैध कर्तव्य और अधिकार है। उन्होंने इस हत्या को बड़ा अपराध बताया और घोषणा की कि ईरान इसे बिना जवाब दिए नहीं छोड़ेगा। राष्ट्रपति ने जोर दिया कि इस घटना से इस्लामी और शिया दुनिया में एक नया अध्याय शुरू होगा, जहां ईरान पूरी ताकत और विश्व के स्वतंत्र लोगों के समर्थन से अपराधियों को पछतावा करवाएगा। ईरान ने पहले ही अमेरिकी ठिकानों और इजरायल पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे क्षेत्रीय तनाव चरम पर पहुंच गया है।

खामेनेई की हत्या और ईरान पर हमले के खिलाफ कई देशों ने जताया विरोध, संयुक्त राष्ट्र ने बताया अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन

नयी दिल्ली। ईरान पर अमेरिका-इजरायली हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गयी है। ईरान पर हमले पर प्रतिक्रिया देने में कई देशों ने जहां शब्दों के चयन में सावधानी बरती है तो कुछ देशों ने खुलकर विरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र समेत रूस, यूरोपीय संघ , चीन, दक्षिण अफ्रीका, उत्तर कोरिया, मलेशिया, चीन, ओमान, इराक आदि देशों ने रविवार को खुले शब्दों में ईरान पर हमले का विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस प्रमुख ने रविवार को ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हवाई हमलों की निंदा की और क्षेत्र तथा दुनिया को 'तबाही के कगार से वापस लाने' के लिए तत्काल बातचीत शुरू करने का आह्वान किया। गुटेरेस ने कहा कि अमेरिका-इजरायल का हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उन्होंने बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने के लिए ईरान के जवाबी हमलों की भी निंदा की। रूस के राष्ट्रपति ब्लादीमिर पुतिन ने तो श्री खामेनेई की हत्या को 'सनक में की गयी' तक बता दिया। रूसी राष्ट्रपति ने श्री खामेनेई की मृत्यु को एक ऐसी हत्या बताया, जिसने 'मानवीय नैतिकता और अंतरराष्ट्रीय कानून के सभी मानदंडों' का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि खामेनेई को रूस में एक 'उत्कृष्ट राजनेता' के रूप में याद किया जायेगा।

चीन ने भी इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग या इसकी धमकी का विरोध और निंदा करता है। सभी को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पालन करना चाहिए।

यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा क्लास ने श्री खामेनेई के निधन को 'ईरान के इतिहास में निर्णायक क्षण' बताया। उन्होंने 'एक्स' कहा कि यूरोपीय संघ तनाव कम करने के लिए व्यावहारिक कदम खोजने पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा, 'आगे क्या होगा यह अनिश्चित है। लेकिन अब एक अलग ईरान के लिए रास्ता खुला है, जिसे आकार देने के लिए वहां के लोगों के पास अधिक स्वतंत्रता हो सकती है। '

मोदी ने 2,700 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन, शिलान्यास

पुडुचेरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 2,700 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और 'बेस्ट पुडुचेरी' के लिए काम करते रहने की प्रतिबद्धता दोहरायी। मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह केंद्र शासित प्रदेश उनके 'बेस्ट पुडुचेरी' यानी व्यापार, शिक्षा, आध्यात्मिकता और पर्यटन पर केंद्रित के दृष्टि की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वह पुडुचेरी के अद्भुत लोगों के बीच आकर प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा कि आज शुरू हुईं परियोजनाएँ प्रदेश के लोगों के जीवन को सुगम बनाने और क्षेत्र में आर्थिक विकास को तेज़ करने में सहायक होंगी। उन्होंने कहा, 'पिछले साढ़े चार वर्षों में, इस दृष्टिकोण ने सुशासन और विकास को जन्म दिया है, जिसका प्रमाण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और देश में सर्वोच्च सामाजिक प्रगति सूचकांक स्कोर है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन किया, जिनमें पीएम ई-बस सेवा पहल के तहत ई-बसों का शुभारंभ, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एकीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर, सिटीज़ (सीआईटीआईएस) पहल के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास इकाइयाँ, तथा पुडुचेरी सरकार की प्रमुख सीवरेज और जल आपूर्ति परियोजनाएं शामिल हैं। ये परियोजनाएँ शहरी गतिशीलता में सुधार, नागरिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार की गयी हैं। उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए श्री मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कराईकल में कॉम्पोजिट इंजीनियरिंग ब्लॉक, डॉ एपीजे अब्दुल कलाम ब्लॉक और गंगा छात्रावास का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने पांडिचेरी विश्वविद्यालय में नए एनेक्सी भवनों, व्याख्यान कक्षों और छात्रावासों का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने देशभर में अवसंरचना विकास को रेखांकित करते हुए इस वर्ष के बजट में आवंटित रिकॉर्ड 12 लाख करोड़ रुपये का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा, 'पुडुचेरी को अब 'राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता' योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, जो पहले केवल राज्यों तक ही सीमित थी; इससे सड़कों, जल आपूर्ति, स्कूलों, अस्पतालों और ऐसी ही कई अन्य परियोजनाओं जैसी आवश्यक अवसंरचना के लिए अधिक धन उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, 'एक मजबूत और सशक्त युवा हमारे देश की विकास की नींव है। हम उनके सपनों को समर्थन देने के लिए काम कर रहे हैं।

पूर्वोत्तर भारत को बंगाल की खाड़ी से जोड़ेगा जापान

● हिंद महासागर तक कनेक्टिविटी में भी मदद की है तैयारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत सरकार पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार मानते हुए क्षेत्र के आठों राज्यों में कनेक्टिविटी पर बहुत जोर दे रही है। यह मोदी सरकार की ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी पर आधारित है। भारत की इस नीति में और ज्यादा सहायता के लिए पुराना और भरोसेमंद मित्र जापान सामने आया है। जापान ने कहा है कि वह पूर्वोत्तर भारत को बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर तक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने में मदद के लिए तैयार है।

जापान के उप विदेश मंत्री होरी इवाओ ने शुक्रवार को कहा कि उनका देश पूर्वोत्तर भारत को बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तक कनेक्टिविटी दिलाने में मदद करने के लिए तैयार है। मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग में एक फॉरन पॉलिसी कॉनक्लेव (सिक्स्थ इंडिया-जापान इंटेलेक्चुअल कॉन्क्लेव) में उन्होंने यह बात कही। इसका आयोजन शिलॉन्ग के एक फॉरन पॉलिसी थिंक टैंक कॉन्फ्लूएंस ने किया।

नागपुर में डेटोनेटर बनाने वाली कंपनी में धमाका, 17 कर्मचारियों की मौत; 18 घायल

नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के काटोल इलाके के पास रविवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। राउलगांव स्थित 'एसबीएल एनर्जी लिमिटेड' नामक विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में हुए एक शक्तिशाली विस्फोट में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह कंपनी खनन और औद्योगिक कार्यों के लिए डेटोनेटर और अन्य विस्फोटक तैयार करती है।

पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह हादसा सुबह 6:00 से 7:00 बजे के बीच हुआ। उस समय फैक्ट्री में सुबह की शिफ्ट के कर्मचारी अपना काम शुरू कर चुके थे। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब डेटोनेटर बनाने की प्रक्रिया चल रही थी तभी अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। नागपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार ने हताहतों की संख्या की पुष्टि करते हुए बताया कि घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कई की हालत चिंताजनक बनी हुई है।

जंग के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तेल टैंकर पर कर दिया हमला, 15 भारतीय क्रू थे सवार

नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट में इजरायल-ईरान के बीच जारी जंग से तनाव चरम पर पहुंच गया है। अली खामेनेई की मौत से दुनियाभर के कई देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच, ईरान ने रविवार को स्ट्रेटेजिक होर्मुज स्ट्रेट में एक ऑयल टैंकर पर हमला किया, जिसमें उसमें सवार चार नाविक घायल हो गए। इस पर 15 भारतीय क्रू भी सवार थे। ओमान के मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर (MSC) के अनुसार, ऑयल टैंकर, स्काईलाइट, 20 लोगों के क्रू के साथ जा रहा था, जिसमें 15 भारतीय और पांच ईरानी नागरिक शामिल थे।

मुसंदम में खासाब पोर्ट से पांच नॉटिकल मील दूर हुए हमले के बाद क्रू को निकाल लिया गया। हमला पलाऊ के झंडे वाले स्काइलाइट नाम के जहाज को निशाना बनाकर किया गया। इसने क्रू के सदस्यों को भारतीय और ईरानी बताया। यह हमला तब हुआ जब अधिकारियों ने कहा कि जब से अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया है, ईरान रेडियो के जरिए स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को धमकी दे रहा है। यह स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण है कि यहीं से दुनियाभर को लगभग 20 फीसदी तेल जाता है। समुद्री अधिकारियों और ईयू नेवल मिशन के एक अधिकारी के मुताबिक, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने जहाजों को चेतावनी दी है कि स्ट्रेटेजिक होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत नहीं है। इस पतले पानी के रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को, जो दुनिया के तेल एक्सपोर्ट का लगभग पांचवां हिस्सा संभालता है, रेडियो ट्रांसमिशन मिले हैं जिसमें उन्हें ईरान पर हाल ही में हुए अमेरिकी-इजरायली हमलों के बाद बढ़ते संघर्ष के बीच ट्रांजिट से बचने के लिए कहा गया है।

संक्षिप्त समाचार

पुस्तक विवाद: सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख से शिक्षा मंत्रालय में हड़कंप

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की आठवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका से जुड़ी विवादास्पद विषयवस्तु को शामिल किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय में गुरुवार को भी हड़कंप देखने को मिली। हर कोई माफी मांगने के लिए तैयार दिखा लेकिन स्थिति अब यह है कि माफी से काम नहीं चलेगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को मिनट्स देने से पहले खुद ही जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी है। गुरुवार को दिन भर शिक्षा मंत्रालय से लेकर एनसीईआरटी के भीतर बैठकों को दौर चलता रहा। गौरलतब है कि सुप्रीम कोर्ट पाठ्यपुस्तक तैयार करने से जुड़ी बैठकों के सारे मिनिट्स मांगे है। मिनिट्स आने के बाद यह साफ हो जाएगा कि यदि विषयवस्तु को कमेटी की बगैर मंजूरी के शामिल किया तो वह भी साफ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गुरुवार को दिए गए निर्देश के बाद शिक्षा मंत्रालय ने तुरंत ही एनसीईआरटी निदेशक को पूरे मामले की जांच कराने के आदेश दिए है। साथ ही यह बताने कहा है कि न्यायपालिका से जुड़ी विवादित विषय वस्तु को किसके कहने से और कैसे शामिल की गई। माना जा रहा है कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मंत्रालय इस मामले पर संबंधित लोगों पर कार्रवाई भी करेगा। यूं तो एनसीइआरटी स्वायत्त है लेकिन इस संभावना से गुरेज नहीं किया जा रहा है कि मंत्रालय के बड़े अधिकारी भी दायरे में आ सकते हैं।

गूगल मैप से जल्द सर्च कर सकेंगे नजदीकी आधार केंद्र, आसान होगी पहुंच

नई दिल्ली, एजेंसी। लोगों को नया आधार कार्ड बनवाने या अपडेट कराने के लिए अब अधिकृत आधार केंद्र की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। जल्द ही गूगल मैप से नजदीकी आधार केंद्र को आसानी से सर्च किया जा सकेगा। इसके लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने तकनीकी दिग्गज गूगल से हाथ मिलाया है। गूगल मैप पर अधिकृत आधार केंद्र दिखाई देंगे। इस पहल से देशभर के लोगों को अधिकृत आधार केंद्रों तक पहुंचने में आसानी होगी और सुविधा में बढ़ोतरी होगी। आधिकारिक बयान के अनुसार, इस पहल से लोगों को विभिन्न सेवाओं को लेकर आधार केंद्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी कि किस केंद्र पर वयस्कों का पंजीकरण होता है। कहां बच्चों का आधार बन सकता है और किस केंद्र पर केवल पता व मोबाइल नंबर को अपडेट कराया जा सकता है। यह सुविधा आने वाले महीनों में उपलब्ध हो जाएगी। गूगल के साथ सहयोग का उद्देश्य जनसुविधा को बढ़ाना, गलत सूचनाओं से बचना और यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों को देशभर में अत्याधुनिक आधार सेवा केंद्रों समेत 60 हजार से अधिक आधार केंद्रों तक निर्बाध पहुंच मिले। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जब यूजर गूगल मैप पर सर्च करेंगे तो उन्हें सत्यापित आधार केंद्रों तक निर्देशित किया जाएगा।

भाजपा की नई टीम में आधे से अधिक बदले जाएंगे, 60 साल से कम उम्र वाले नेताओं को मौका

नई दिल्ली , एजेंसी। भाजपा में नए युवा अध्यक्ष आने के बाद अब राष्ट्रीय संगठन को भी युवा आकार दिए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। महासचिव एवं सचिव स्तर पर 60 साल से कम आयु वाले नेताओं को तरजीह दी जाएगी। हालांकि, उपाध्यक्ष के स्तर पर जरूर अनुभवी वरिष्ठ नेताओं को जगह मिलने की संभावना है। पार्टी में आधे से ज्यादा नए पदाधिकारियों के आने की संभावना है, जिनमें से लगभग आधे विभिन्न राज्यों से केंद्रीय संगठन में लाए जाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर युवा नितिन नवीन के आने के बाद उनकी टीम में भी नए तथा अपेक्षाकृत युवा नेताओं को जगह मिलने की प्रबल संभावना है। सूत्रों के अनुसार, भविष्य की भाजपा तैयार करने के लिए अध्यक्ष समेत 40 राष्ट्रीय पदाधिकारियों में लगभग 60 फीसदी नए चेहरे होंगे। महासचिव एवं सचिव स्तर पर 60 साल से कम आयु के पदाधिकारियों की नियुक्ति किए जाने की संभावना है। उपाध्यक्ष स्तर पर आयु को लेकर कुछ लचीलापन रह सकता है ताकि संगठन में अनुभवी नेताओं को समायोजित किया जा सके।

गेहूं-सरसों की उन्नत किस्में और स्मार्ट मशीनें बनीं आकर्षण, भविष्य की खेती का रूख कर रहे किसान

नईदिल्ली, एजेंसी। पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर में आयोजित हो रहे कृषि विज्ञान मेला में इस बार किसानों के लिए मेला केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि भविष्य की खेती की पाठशाला बनता नजर आ रहा है। मेले के दूसरे दिन भी यहां बड़ी संख्या में किसान व कृषि में रुचि रखने वाले लोग जुटे। यहां आए लोगों व किसानों का सबसे अधिक ध्यान गेहूं और सरसों की उन नई किस्मों ने खींचा है, जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच अधिक पैदावार का भरोसा दे रही हैं।

खेतों में सीधी जानकारी: गेहूं और सरसों की नई धमक

मेले के मुख्य प्रदर्शनी स्थल में गेहूं की नई किस्मों, एचडी 3385 जो नई और क्रांतिकारी किस्म मानी जा रही है, के बारे में किसान खूब दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यह किस्म जल्द बुवाई के लिए सबसे उपयुक्त है। इसकी बुवाई 20 अक्टूबर के आसपास की जा सकती है। यह मार्च की अचानक गर्मी को झेल लेती है और दाना सूखता नहीं है। इसी तरह एचडी 3386 इसे हाल ही में अधिसूचित किया गया है और यह उत्तर-पश्चिमी मैदानी इलाकों के लिए बेहतरीन है। इस किस्म में खेत में लहलहाता देख किसानों को आश्चर्य होता है। यह किस्म पीला रतुआ और भूरा रतुआ जैसी बीमारियों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है। इसका तना मजबूत होता है, जिससे तेज हवा चलने पर भी फसल गिरती नहीं है। इसी तरह एचडी-3385 और एचडी-3226, को देखने के लिए किसानों की लंबी कतारें लगी रहीं। किसान केवल दूर से फसल देख नहीं रहे हैं, बल्कि विज्ञानियों के साथ सीधे संवाद कर रहे हैं। संवाद के दौरान विज्ञानी किसानों को यह बताना नहीं भूल रहे हैं कि ने बताया कि गेहूं की ये नई किस्में कम समय में पकने और मार्च-अप्रैल की हीट वेव यानि लू को झेलने में सक्षम हैं।

सरसों की बात करें तो पूसा डबल जीरो मस्टर्ड 31 और 33 जैसी किस्मों ने किसानों को प्रभावित किया है। इन किस्मों की खासियत यह है कि इनमें यूरिसिक एसिड की मात्रा बहुत कम है, जो इसे स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम बनाती है।

मेले का दूसरा बड़ा आकर्षण खेती की नई मशीनरी रही। अब किसान हल-बैल के दौर से निकलकर स्मार्ट मशीनरी की ओर रुख कर रहे हैं। प्रदर्शनी में लगे एग्री-ड्रोन को लेकर युवाओं और प्रगतिशील किसानों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। ये ड्रोन मात्र कुछ ही मिनटों में एक एकड़ खेत में नैनो यूरिया या कीटनाशकों का छिड़काव कर सकते हैं। मशीनरी स्टाल्स पर मौजूद विशेषज्ञों ने बताया कि लेजर लैंड लेवलर, हैप्पी सीडर और मल्चर जैसी मशीनों के प्रति किसानों की रुचि बढ़ी है। ये मशीनें न केवल मजदूरी का खर्च बचाती हैं, बल्कि पराली प्रबंधन और पानी की बचत में भी क्रांतिकारी बदलाव ला रही हैं। छोटे किसानों के लिए कम कीमत वाले पावर टिलर और बुवाई यंत्र भी विशेष रूप से प्रदर्शित किए गए हैं।

पूसा मेले की सबसे बड़ी खूबी आमने-सामने का संवाद है। पंडालों में चल रहे सत्रों में किसान अपनी मिट्टी की जांच रिपोर्ट और फसलों में लगने वाली बीमारियों की तस्वीरें लेकर पहुंच रहे हैं। विज्ञानियों द्वारा किसानों को जैविक खाद के उपयोग, ड्रिप सिंचाई और फसल विविधीकरण के फायदे समझाए जा रहे हैं। पूसा कृषि विज्ञान मेले में इस बार सबसे ज्यादा गहमागहमी बीज बिक्री काउंटरों पर देखने को मिल रही है। नई विकसित किस्मों, विशेषकर गेहूं और सरसों की उन्नत प्रजातियों के प्रामाणिक बीज पाने के लिए किसान काफी उत्सुक नजर आए। किसानों में उत्साह इस कदर है कि वे विज्ञानियों से बीजों की शुद्धता और बुवाई की तकनीक समझने के बाद तुरंत खरीदारी कर रहे हैं। किसानों का मानना है कि बाजार के असुरक्षित बीजों के मुकाबले पूसा के प्रमाणित बीज न केवल बेहतर अंकुरण देते हैं, बल्कि प्रतिकूल मौसम में भी पैदावार की गारंटी देते हैं।

जल बोर्ड बिल भेजता है तो साफ पानी क्यों नहीं देता?

नईदिल्ली, एजेंसी। बुराड़ी में पीने के पानी को लेकर लंबे समय से मारामारी की स्थिति है। कहीं नियमित पेयजल आपूर्ति न होने की शिकायत है तो कहीं दूषित जलापूर्ति को लेकर लोग परेशान हैं। आधा दर्जन से अधिक कालोनियों के नल गंदा-बदबूदार पानी उगल रहे हैं। दूषित जलापूर्ति के कारण लोग पानी खरीदकर पीने को मजबूर हैं। सुबह-शाम वाहनों पर और कंधे पर पानी के कैंपर ले जाते लोग आसानी से देखने को मिल जाएंगे। दूषित जलापूर्ति व जल संकट के कारण क्षेत्र में पानी का धंधा तेजी से फल-फूल रहा है। लोगों का कहना है कि जल बोर्ड बिल तो नियमित रूप से भेज देता है, लेकिन साफ पानी उपलब्ध कराने में नाकाम है। सत्य विहार, संत नगर, बुराड़ी गांव, बाबा कॉलोनी, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, नत्थू कॉलोनी, अजित विहार व गौरव विहार सहित तमाम रिहायशी क्षेत्रों में पीने के पानी किल्लत बनी हुई है। आमतौर पर यहां घरों में पानी की फिल्टर मशीन लगी हुई हैं। पानी की गुणवत्ता इतनी खराब है कि फिल्टर और आरओ भी जवाब दे जाते हैं। पानी की खराब गुणवत्ता होने की वजह से बहुत जल्द ही खराब हो जाती है। जबकि यहां पानी बेचने का व्यापार भी धड़ल्ले से चलता है। दूषित जलापूर्ति की वजह से मजबूरन लोगों निजी प्लांटों से पानी खरीदकर पीना पड़ता है। इन प्लाटों पर 10 से 40 रुपये तक 20 लीटर स्वच्छ जल लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। बुराड़ी के सत्य विहार में पिछले लगभग 10 वर्ष से पहले पानी की पाइप लाइन डाली गई। लेकिन आज तक लोगों को स्वच्छ जल मुहैया नहीं कराया गया। कालोनी में लगभग 25 में से पांच गलियों में पानी आता ही नहीं। जबकि अन्य 20 गलियों में नलों से दूषित जलापूर्ति होती है। इस वजह से कॉलोनी में रहने वाले लगभग 10 हजार लोग परेशान हैं। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अमित सक्सेना ने बताया कि बुराड़ी की लगभग 70 प्रतिशत कालोनियों में पानी की समस्या है। जिसका समाधान आज नहीं हो सका। मैं 20 वर्षों कॉलोनी में रह रहा हूं। लेकिन पाइप लाइन के बाद आज साफ पानी आया ही नहीं। सरकार साफ पानी मुहैया करा नहीं सकती। लेकिन बिल जरूर लेती है। मेरा 1900 रुपये का बिल आया है। जबकि पानी साफ आता नहीं। पानी साफ न आने की वजह से 10 से 15 रुपये का 20 लीटर पानी मंगाना पड़ता है। दूषित जल की वजह से काफी दिक्कत होती है। यदि सप्लाई के पानी से नहा लेते हैं तो खुजली व एलर्जी हो जाती है।

प्रदर्शन में महिला की मौत पर दिल्ली एचसी का फैसला, केंद्र सरकार और हयात से मुआवजे की मांग ठुकराई

नई दिल्ली, एजेंसी। नेपाल में गत वर्ष हुए जेन-जी के प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार की लापरवाही से महिला की मौत के मामले में मुआवजे की मांग वाली याचिका पर विचार करने से हाई कोर्ट ने गुरुवार को इनकार कर दिया। गाजियाबाद निवासी व्यापारी रामबीर सिंह गोला ने याचिका दायर कर संवेदनशील देशों की यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए केंद्र द्वारा एक सही प्रोटोकॉल बनाने के लिए निर्देश देने की मांग की थी। हालांकि, न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि मामले पर निर्णय के लिए तथ्यों और कानून के विवादित सवालों पर फैसला लेना होगा। अदालत ने याचिकाकर्ता को दूसरे कानूनी उपाय कर उपयोग करने को कहा। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता से अदालत की सहानुभूति है और लेकिन इसके लिए जनहित याचिका दायर करना बेहतर उपाय है। अदालत के रुख को देखते हुए याचिका वापस ले ली। याचिकाकर्ता ने विरोध-प्रदर्शन के दौरान नौ सितंबर 2025 को अपनी पत्नी की मौत के लिए केंद्र सरकार 25 करोड़ रुपये और हयात होटलों से 75 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी। साथ ही घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग के गठन की मांग की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि बार-बार फोन करने और खतरे का अंदाजा होने के बावजूद भारतीय दूतावास या विदेश मंत्रालय ने कोई मदद नहीं की।

यूपी-बिहार से लेकर एमपी और राजस्थान तक पारा 30 के पार, पहाड़ी राज्यों में बारिश-बर्फबारी की चेतावनी

नई दिल्ली, एजेंसी। फरवरी के आखिरी सप्ताह में मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोत्तरी के साथ गर्मी अपना असर दिखाना शुरू कर रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के कई शहरों में तापमान 30डिग्री के पार चला गया है। वहीं, आज कई राज्यों में बारिश का भी अलर्ट जारी है। आइए जानते हैं देशभर के मौसम का हाल... मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। गुजरात और महाराष्ट्र के तापमान में भी इजाफा देखने को मिलेगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज, यानी 27 फरवरी को 6 राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है।

दिल्ली-एनसीआर का मौसम: अगर बात करें दिल्ली एनसीआर के मौसम की तो यहां तेज हवाओं के कारण लोगों को प्रदूषण से काफी हद तक राहत मिली है। दिन में धूप खिली रहेगी। यहां 27 फरवरी को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री तथा 28 फरवरी को अधिकतम 32 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री

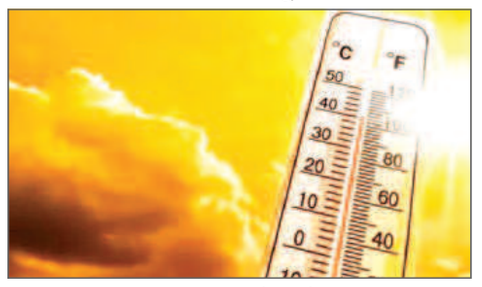

सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान के कई शहरों में तापमान 30एष्ट के पार चला गया है। 26 फरवरी को राजस्थान कई इलाकों में दिन का अधिकतम तापमान 37एष्ट से ऊपर चला गया। बाड़मेर में सबसे ज्यादा तापमान 36.3एष्ट दर्ज किया गया। वहीं, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर में भी सामान्य से अधिक गर्मी महसूस हुई। मध्य प्रदेश में तीखी धूप देखने को मिल रही है। यहां तापमान 27एष्ट से 32एष्ट के बीच दर्ज हो रहा है। कल भोपाल और इंदौर जैसे प्रमुख शहरों में तापमान 29 से 30 डिग्री के आसपास रहा, जबकि बुरहानपुर जैसे दक्षिणी क्षेत्रों में पारा 32 डिग्री तक पहुंच गया।

उत्तर प्रदेश का मौसम: अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मौसम की तो फिलहाल यहां बारिश की कोई संभावना नहीं है। अधिकांश जिलों में धूप खिलेगी। तापमान में बढ़ोत्तरी जारी रहेगी। यूपी के जिन जिलों में पारा बढ़ने वाला है, उनमें कानपुर,मेरठ, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़,इटावा,मैनपुरी, मथुरा, अमेठी, आजमगढ़, अमरोहा,बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर शामिल हैं। कई जिलों में तापमान 30 डिग्री के पार पहुंच चुका है।

बांग्लादेश आर्मी हेडक्वार्टर में हलचल तेज

ढांका, एजेंसी। बांग्लादेश में नई सरकार के सत्ता संभालने के बाद एक सप्ताह के अंदर दूसरा बड़ा फेरबदल किया गया है। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल डिफेंस कॉलेज के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शाहीनुल हक को क्वार्टरमास्टर जनरल के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया है। बांग्लादेश में नई सरकार गठन के बाद से ही बैक टू बैक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। यूं कहें तो बांग्लादेश इस वक्त बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इस बीच बांग्लादेश सेना में उच्च कमान के प्रमुख पदों पर बड़े बदलाव किए गए हैं। नई सरकार के सत्ता संभालने के बाद एक सप्ताह के अंदर यह दूसरा ऐसा बड़ा फेरबदल है। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल डिफेंस कॉलेज (एनडीसी) के कमांडेंट लेफ्टिनेंट

टॉप कमांड में बड़े बदलाव; प्लान क्या है?

जनरल मोहम्मद शाहीनुल हक को क्वार्टरमास्टर जनरल के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया है। एनडीसी में उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान ने ली है, जो पहले क्यूएमजी के पद पर थे। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि 19वीं इन्फैंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग और घटाईल एरिया कमांडर मेजर जनरल हुसैन अल मोशेंद को सेना मुख्यालय में नया एडजुटेंट जनरल नियुक्त किया गया है। वहीं, मौजूदा एडजुटेंट जनरल मेजर जनरल मोहम्मद हकीमुज्जमान को मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नया कमांडेंट बनाया गया है। एमआईएसटी के पूर्व कमांडेंट मेजर जनरल मोहम्मद नसीम परवेज को विदेश मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। सेना के अन्य पुनर्गठन के तहत, 66 इन्फैंट्री डिवीजन के जीओसी और रंगपुर एरिया कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद कामरुल हसन को ढाका छावनी में लॉजिस्टिक्स एरिया के जीओसी और एरिया कमांडर बनाया गया है। ढाका छावनी में लॉजिस्टिक्स एरिया के पूर्व प्रमुख मेजर जनरल मुहम्मद मोस्टागौसुर रहमान खान नियमित शर्तों पर सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आरोप- बांग्लादेश सरकार ने डिफाल्टर को सेंट्रल बैंक गवर्नर बनाया

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश में सेंट्रल बैंक के नए गवर्नर की नियुक्ति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि तारिक रहमान की सरकार ने एक डिफाल्टर को कारोबारी को सेंट्रल बैंक गवर्नर बना दिया है, जो देश में भीड़तंत्र की शुरुआत जैसा है।

बांग्लादेश बैंक के नए गवर्नर के रूप में मोस्ताकुर रहमान की नियुक्ति के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया। जमात ए इस्लामी के प्रमुख और विपक्ष के नेता शफीकुर रहमान ने कहा कि यह फैसला पीएम की शह पर लिया गया है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इससे पहले सरकार ने अहसान हबीब मंसूर का कार्यकाल अचानक खत्म कर दिया था, जिन्हें मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने नियुक्त किया था। मंसूर ने कहा कि उन्होंने न इस्तीफा दिया और न ही उन्हें हटाए जाने की कोई आधिकारिक सूचना मिली। उन्हें यह खबर मीडिया के जरिए पता चली। मोस्ताकुर रहमान की नियुक्ति इसलिए अलग मानी जा रही है क्योंकि अब तक बांग्लादेश में केंद्रीय बैंक का गवर्नर आमतौर पर अनुभवी बैंकर, अर्थशास्त्री या वरिष्ठ सिविल सेवक होते रहे हैं। मोस्ताकुर एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और गारमेंट कारोबारी हैं। वे हेरा स्वेटर्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और हालिया चुनाव में तारिक रहमान की बीएनपी पार्टी की केंद्रीय चुनाव संचालन समिति से भी जुड़े रहे थे।

किम जोंग-उन की साउथ कोरिया को चेतावनी, बोले- खतरा हुआ तो 'पूरी तरह तबाह' कर देंगे

प्योंगयांग, एजेंसी। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग-उन ने साउथ कोरिया को कड़ी चेतावनी दी है। किम ने कहा है कि उनके देश की सुरक्षा को खतरा हुआ तो वे साउथ कोरिया को 'पूरी तरह नष्ट' कर सकते हैं। प्योंगयांग में सात दिन चली वर्कर्स पार्टी कांग्रेस के समापन पर किम ने अगले पांच वर्षों के लिए परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को तेज करने का खाका पेश किया। उन्होंने पानी के भीतर से दागे जा सकने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सामरिक परमाणु हथियारों के विस्तार, परमाणु-संचालित पनडुब्बी, एआई-युक्त ड्रोन और उन्नत उपग्रह विकसित करने की बात कही। किम ने साउथ कोरिया को 'स्थायी दुश्मन' बताते हुए कहा कि उससे बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं, उन्होंने कहा कि अमेरिका यदि प्रतिबंध और दबाव की नीति छोड़े तो संवाद संभव है। कांग्रेस के बाद राजधानी में भव्य सैन्य परेड आयोजित की गई, जिसमें किम अपनी बेटी के साथ नजर आए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि किम एक ओर अपने परमाणु कार्यक्रम को मजबूती दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिका के साथ भविष्य की संभावित बातचीत के लिए विकल्प भी खुले रख रहे हैं।

इजरायल में थे पीएम मोदी, इधर पाकिस्तान की नींद हराम हो गई

इजरायल, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया इजरायल दौरे ने वैश्विक कूटनीति में बड़ी हलचल पैदा कर दी है, और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ोसी देश पाकिस्तान पर देखने को मिल रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा एक नए हेक्सागन अलायंस की घोषणा के बाद से ही पाकिस्तान में बौखलाहट का माहौल है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने एक ताजा बयान जारी कर इस गठबंधन को इस्लामी दुनिया के खिलाफ एक साजिश करार दिया है और खुले तौर पर अपनी सुरक्षा को लेकर डर जाहिर किया है।

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय (स्नह) ने गुरुवार को कहा कि वह भारत और इजरायल के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग पर करीबी नजर

रखे हुए है। यह बयान ऐसे समय आया है जब प्रधानमंत्री मोदी की हालिया इजरायल यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रक्षा, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की घोषणा की है।

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत द्वारा इजरायली रक्षा प्रणालियों और प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल को लेकर इस्लामाबाद सतर्क है। उनके अनुसार- हम अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए उत्पन्न खतरे से पूरी तरह अवगत हैं।

पाकिस्तान की बौखलाहट की मुख्य वजह- हेक्सागन अलायंस

पीएम मोदी के दौरे के दौरान, बेंजामिन नेतन्याहू ने एक नए रणनीतिक गुट की रूपरेखा दुनिया के सामने रखी, जिसने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है।

गठबंधन में कौन-कौन- नेतन्याहू ने ऐलान किया कि इस हेक्सागन अलायंस में इजरायल के साथ भारत, ग्रीस और साइप्रस मुख्य रूप से शामिल होंगे। इसके अलावा कुछ अरब, अफ्रीकी और एशियाई देशों के भी इसमें जुड़ने की बात कही गई है, हालांकि उनके नामों का खुलासा नहीं किया गया है।

इजरायली पीएम ने स्पष्ट किया कि यह अलायंस मिलकर इस्लामी कट्टरपंथी दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगा।

नेतन्याहू के इस ऐलान के तुरंत बाद, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना डर और विरोध दर्ज कराया था। अंद्राबी ने इस नए अलायंस को सीधे तौर पर मुस्लिम देशों के खिलाफ एक सोची-समझी साजिश बताया है। पाकिस्तान का मानना है कि कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई की आड़ में इस गठबंधन का असली निशाना मुस्लिम राष्ट्र हैं।

पाकिस्तान ने खुले तौर पर माना है कि उसे इस गुट से खतरा है। अंद्राबी ने कहा- हम उन खतरों से पूरी तरह वाकिफ हैं, जो वे (अलायंस के देश) हमारी सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ-साथ क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए पैदा करते हैं। अपने डर को छिपाने और अपनी आवाम को ढांढस बंधाने के लिए अंद्राबी ने आगे जोड़ा- हम बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने दुश्मन ताकतों के किसी भी संभावित हमले को रोकने के लिए अपनी सैन्य तैयारियां पूरी तरह से मजबूत रखी हैं।

भारत, यूरोपीय संघ के व्यापार समझौते में मध्यस्थता से जुड़ा परिशिष्ट शामिल

- समझौते पर विधिक परीक्षण के बाद हस्ताक्षर होने की संभावना

नई दिल्ली।

भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने हाल ही में बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के निष्कर्ष की घोषणा की। समझौते पर विधिक परीक्षण के बाद हस्ताक्षर होने की संभावना है और इसे अगले वर्ष लागू किया जा सकता है। एफटीए में मॉडल मध्यस्थता प्रक्रिया पर एक अलग परिशिष्ट शामिल है, जिसका उद्देश्य विवादों का त्वरित और आपसी सहमति से समाधान करना है। समझौते के अनुसार भारत या ईयू कोई भी पक्ष ऐसे उपाय के खिलाफ मध्यस्थता की मांग कर सकता है, जो द्विपक्षीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो।

हालांकि प्रक्रिया केवल दोनों पक्षों की आपसी सहमति से ही शुरू होगी। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमति नहीं बनती, तो मध्यस्थता का अनुरोध स्वतः निरस्त माना जाएगा। मध्यस्थता आम तौर पर उस पक्ष के क्षेत्र में होगी, जिसके पास अनुरोध भेजा गया है, या आपसी सहमति से किसी अन्य स्थान या माध्यम से भी इसे आयोजित किया जा सकता है।

मध्यस्थ की नियुक्ति के 60 दिनों के भीतर समाधान तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। करीब दो दशक चली वार्ताओं के बाद संपन्न एफटीए के तहत भारत के 93 प्रतिशत निर्यात को 27 देशों में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी, जबकि ईयू से लक्जरी कार और वाइन का आयात सस्ता होगा। दोनों पक्ष वैश्विक जीडीपी का लगभग 25 प्रतिशत और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक-तिहाई हिस्सा नियंत्रित करते हैं।

समझौते में कुल 20 अध्याय शामिल हैं, जिनमें डिजिटल व्यापार पर अलग अध्याय भी है। यह कागज-रहित व्यापार, नियामकीय सहयोग और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देता है।

इसके अलावा विवाद निपटान पर अलग अध्याय विवादों के शीघ्र और प्रभावी समाधान की व्यवस्था करता है।

फरवरी में सीमेंट की औसत कीमत 342 रुपये प्रति बोरी पहुंची

- कुछ राज्यों में मार्च में फिर बढ़ोतरी की तैयारी

नई दिल्ली ।

फरवरी में सीमेंट बाजार ने मिलीजुली तस्वीर पेश की। जनवरी में बढ़ी कीमतों के बाद उम्मीद थी कि रुझान और मजबूत होगा, लेकिन स्थिति न तो बहुत तेज रही और न ही पूरी तरह सुस्त। पूरे देश में औसत ट्रेड कीमत 2 रुपये बढ़कर 342 रुपये प्रति बोरी हो गई। क्षेत्रीय तौर पर हालात अलग रहे। पश्चिम भारत में दाम 7 रुपये प्रति बोरी तक बढ़कर सबसे मजबूत प्रदर्शन किया। पूर्व में 4 रुपये और उत्तर में 3 रुपये की तेजी रही। मध्य भारत में कीमतें लगभग स्थिर रहीं, जबकि दक्षिण भारत में औसतन 2 रुपये प्रति बोरी की गिरावट दर्ज की गई। कुछ बाजारों में महीने की शुरुआत में बढ़ी कीमतें बाद में सामान्य हो गईं। जनवरी और फरवरी मिलाकर चालू तिमाही में औसत दाम पिछली तिमाही से करीब 1 प्रतिशत अधिक रहे। इससे कंपनियों को थोड़ी राहत मिली। बाजार को इस बार बड़े निर्माण और सरकारी प्रोजेक्ट्स का सहारा मिला। खुदरा बाजार में दाम 0 से 15 रुपये प्रति बोरी ऊपर-नीचे रहे, जबकि बड़े ऑर्डर वाले सौदों में 0 से 20 रुपये तक बढ़त दर्ज हुई। ज्यादातर जगहों पर मांग जनवरी की तुलना में बेहतर रही, लेकिन खुदरा खरीदार अभी पूरी ताकत से नहीं उतरे। मार्च के पहले 10 दिन होली के कारण कामकाज धीमा रह सकता है। मार्च में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना ज्यादातर इलाकों में कम है। हालांकि बिहार, पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में 10-15 रुपये प्रति बोरी तक दाम बढ़ाने की तैयारी चल रही है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल मांग ठीक है, इसलिए अचानक बड़ी गिरावट की संभावना कम है। असली परीक्षा यह होगी कि कंपनियां बढ़े हुए दाम को कितने समय तक संभाल पाती हैं।

क्रेडिट कार्ड नियमों में संभावित बदलाव 1 अप्रैल से

क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को पहचान और पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने पर विचार

नई दिल्ली। क्रेडिट कार्ड अब आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरत बन चुके हैं। खरीदारी, यात्रा, ऑनलाइन बिल और टैक्स भुगतान में उनका उपयोग तेजी से बढ़ा है। 1 अप्रैल से इन कार्डों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव हो सकते हैं, जो सीधे उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करेंगे। नए नियमों के तहत सालभर में किए गए बड़े भुगतान पर विशेष नजर रखी जा सकती है। यदि कोई निर्धारित सीमा से अधिक क्रेडिट कार्ड बिल जमा करता है, तो इसकी जानकारी संबंधित विभाग को दी जा सकती है। इसका उद्देश्य वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता और अनियमित गतिविधियों पर नियंत्रण रखना है। डिजिटल और नकद भुगतान के लिए अलग-अलग सीमा तय की जा सकती है। तय सीमा से अधिक नकद जमा करने पर इसकी रिपोर्टिंग अनिवार्य हो सकती है। इससे बड़ी रकम को बिना रिकॉर्ड के चुकाना मुश्किल होगा और नकद भुगतान करने वालों को पहले से योजना बनानी होगी। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को पहचान और पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने पर विचार किया जा रहा है। यह नए कार्ड आवेदन या अपडेट के समय लोगों को अतिरिक्त विकल्प देगा, खासकर उनके लिए जिनके पास सीमित दस्तावेज हैं। सरकार कार्ड को टैक्स और जीएसटी भुगतान के लिए आधिकारिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम बनाने की तैयारी कर रही है। हालांकि प्रोसेसिंग शुल्क लग सकता है। कंपनियों द्वारा दिए गए कॉर्पोरेट कार्ड पर भी खर्च का पूरा रिकॉर्ड रखना और निजी व ऑफिस खर्च अलग दिखाना अनिवार्य हो सकता है। नए कार्ड के लिए पैन नंबर अनिवार्य हो सकता है। कार्डधारकों को बड़े लेन-देन की सीमा, नकद भुगतान नियम, प्रोसेसिंग फीस और खर्च का रिकॉर्ड ध्यान से रखना चाहिए।

तेल की कीमतें भू-राजनीतिक तनाव में मारती हैं उछाल

नई दिल्ली ।

पिछले 50 वर्षों में बड़े युद्ध और भू-राजनीतिक संकट अक्सर कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल लाते रहे हैं। 1970 के दशक में अरब देशों द्वारा निर्यात रोकने से तेल 3 से 12 डॉलर तक बढ़ा। 1990 में इराक-कुवैत युद्ध और 2003 में दूसरे इराक युद्ध में भी कीमतें 40 फीसदी तक बढ़ीं, लेकिन सप्लाई बढ़ने पर जल्द सामान्य हुईं। 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान तेल 80 से डालर 120 प्रति बैरल तक गया, फिर वैकल्पिक खरीदारों के आने से छह महीनों में दाम सामान्य हुए। विशेषज्ञों के अनुसार, ईरान का उत्पादन वैश्विक तेल सप्लाई का केवल 3 फीसदी है, लेकिन इसका भू-राजनीतिक महत्व बड़ा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते दुनिया की लगभग 20 फीसदी तेल और गैस सप्लाई गुजरती है। इस मार्ग में कोई बाधा आने पर सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई की सप्लाई सीधे प्रभावित हो सकती है। हाल के तनाव के कारण कीमतों में लगभग 10 फीसदी की तेजी देखी गई। विश्लेषकों का कहना है कि हर 1 फीसदी सप्लाई झटके से तेल की कीमत 3-5 फीसदी बढ़ती है। अगर ईरान का 3.3 मिलियन बैरल प्रति दिन उत्पादन रुकता है, तो 70 डॉलर के बेस प्राइस पर दाम 76-81 डॉलर तक जा सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर गंभीर खतरे के मामले में अतिरिक्त जोखिम प्रीमियम 20-40 डॉलर जुड़ सकता है, जिससे कीमत 95-110 डॉलर या उससे ऊपर पहुंच सकती है। इतिहास और विशेषज्ञों की राय यही दर्शाती है कि तेल की कीमतें भू-राजनीतिक तनाव में तेजी दिखा सकती हैं, लेकिन वास्तविक सप्लाई बाधा अक्सर अस्थायी होती है। बाजार में भय और अनिश्चितता ही दामों को अस्थायी रूप से ऊंचा करती है, जबकि संतुलन बहाल होने पर कीमतें सामान्य स्तर पर लौट आती हैं।

पीपीएफ में एक व्य क्ति अपने नाम पर खोल सकता है केवल एक खाता

- संयुक्त खाते की अनुमति भी नहीं

नई दिल्ली ।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) भारत में सबसे भरोसेमंद बचत योजनाओं में से एक है। वित्त मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बचत संस्थान के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक ही पीपीएफ खाता खोल सकता है। यह खाता बैंक में हो या डाकघर में, फर्क नहीं पड़ता। संयुक्त खाते की अनुमति भी नहीं है। अगर किसी के नाम पर एक से अधिक खाते पाए जाते हैं, तो अतिरिक्त खाते को अनियमित माना जा सकता है और उसमें जमा राशि बिना ब्याज के वापस की जा सकती है। पीपीएफ खाते व्यक्ति के पैन नंबर से लिंक होते हैं। इसलिए अलग-अलग बैंक या डाकघर में खाते खोलकर अधिक टैक्स फायदा लेने की कोशिश सिस्टम में पकड़ी जा सकती है। अभिभावक अपने नाबालिग बच्चे या मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति के लिए पीपीएफ खाता खोल सकता है। लेकिन नियम स्पष्ट करते हैं कि एक बच्चे पर सिर्फ एक खाता ही खोला जा सकता है और दूसरे अभिभावक को उसी बच्चे के नाम पर खाता खोलने की अनुमति नहीं है। पीपीएफ में न्यूनतम जमा 500 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए प्रति वित्त वर्ष है। यह सीमा कुल मिलाकर लागू होती है, यानी अभिभावक अपने खाते और नाबालिग बच्चों के खातों में मिलाकर भी 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं जमा कर सकता। नाबालिग खाते खोलने से कुल टैक्स लाभ की सीमा बढ़ती नहीं है। पीएफ योजना लंबी अवधि के लिए डिज़ाइन की गई है। एक से अधिक खाते खोलकर अधिक टैक्स लाभ लेने की कोशिश नियमों के खिलाफ है। अगर निवेशक 1.5 लाख रुपये से अधिक बचत करना चाहता है, तो उसे अन्य वित्तीय साधनों में निवेश करना होगा।

टाटा संस में चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल पर फैसला टला

- प्रस्ताव को लेकर समूह में मतभेद की अटकलें बढ़ीं

नई दिल्ली । टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल को लेकर निदेशक मंडल ने फैसला टाल दिया। यह बैठक ऐसे समय हुई जब टाटा ट्रस्ट, जो टाटा संस में 66 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है, ने पिछले साल सर्वसम्मति से उन्हें तीसरा कार्यकाल देने की सिफारिश की थी। सूत्रों के अनुसार टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा ने पुनर्नियुक्ति को लेकर कुछ शर्तें रखी थीं, जो इस प्रकार हैं- एयर इंडिया का अधिग्रहण और कंपनी के घाटे को लेकर चिंता, सेमीकंडक्टर और बैटरी उत्पादन जैसे नए क्षेत्रों में भारी पूंजीगत जोखिम, नियामकीय बाध्यता और टाटा संस को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने संबंधी स्पष्ट आश्वासन की मांग। इन शर्तों और चिंताओं के कारण बोर्ड ने निर्णय को स्थगित कर दिया। टाटा ट्रस्ट का सर्वसम्मत प्रस्ताव अभी भी कायम है लेकिन पर्यवेक्षकों ने सवाल उठाया कि क्या ट्रस्ट के नामित निदेशक निदेशक मंडल में अलग रुख अपना सकते हैं। यह स्थिति समूह के उच्चस्तरीय मतभेद और रणनीतिक चिंताओं का संकेत देती है।

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया होली ऑफर्स का ऐलान; शॉपिंग और ट्रैवल पर मिलेगी भारी छूट

क्रेडिट और डेबिट कार्ड ग्राहकों के लिए फेस्टिव सीजन में बचत का अवसर; 31 मार्च तक वैध रहेंगे ऑफर्स

मुंबई/इंदौर । भारत के सबसे बड़े स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू एसएफबी ने रंगों के त्योहार होली के उपलक्ष्य में अपने ग्राहकों के लिए विशेष फेस्टिव ऑफर्स की घोषणा की है। बैंक ने ग्रोसरी, फैशन शॉपिंग और ट्रैवल जैसी प्रमुख श्रेणियों में कैशबैक और डिस्काउंट के माध्यम से बचत के अवसर प्रदान किए हैं। यह पहल उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर की गई है जो त्योहार के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए खरीदारी और यात्रा की योजना बना रहे हैं। बैंक द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, ग्रोसरी श्रेणी में स्विगी इंस्टामार्ट पर 111 रू. तक की छूट और ब्लिंकिट, जेप्टो व जियोमार्ट पर एयू क्रेडिट कार्ड के जरिए 5त्न की बचत की जा सकती है। फैशन शॉपिंग के लिए एजीओ (AJIO) पर 10त्न की विशेष छूट उपलब्ध है। वहीं, घर जाने या पर्यटन की योजना बना रहे ग्राहकों को रेडबस और अभिबस पर एयू क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 10त्न तक की राहत मिलेगी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसे हाल ही में यूनिवर्सल बैंक में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है, अपने इन ऑफर्स के जरिए ग्राहकों के त्योहारी खर्च को किफायती बनाना चाहता है। ये सभी विशेष लाभ लाइव हो चुके हैं और ग्राहक इनका फायदा 31 मार्च 2026 तक उठा सकते हैं। बैंक का उद्देश्य उत्सव के इस माहौल में अपने कार्ड धारकों को वित्तीय लचीलापन और बेहतर बैंकिंग अनुभव प्रदान करना है।

सोने की बढ़ती कीमतों से गोल्ड लोन बाजार में रिकॉर्ड उछाल

- जनवरी में गोल्ड लोन में 128 फीसदी की जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई

नईदिल्ली ।

सोने की कीमतों में तेज बढ़ोतरी का सीधा असर बैंकिंग सेक्टर में दिखाई दे रहा है। जनवरी में गोल्ड लोन में 128 फीसदी की जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो पिछले साल जनवरी (91 फीसदी) से काफी अधिक है। रिजर्व बैंक आफ इं डिया (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, गोल्ड जूलरी के बदले बैंकों का आउटस्टैंडिंग लोन पहली बार 4,00,517 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। सोने की कीमतों में 152 फीसदी की बढ़ोतरी ने इस लोन की मांग को मजबूत आधार दिया है। बैंक क्रेडिट में गोल्ड लोन की हिस्सेदारी 9 फीसदी रही। जनवरी में कुल बैंक क्रेडिट ग्रोथ 14.4 फीसदी रही। पर्सनल लोन बैंक क्रेडिट का सबसे बड़ा सेगमेंट बना, जिसमें हिस्सेदारी 34.5 फीसदी रही। रिटेल लोन में 15 फीसदी की तेजी आई, जबकि एजुकेशन लोन दूसरे सबसे तेज बढ़ने वाले सेगमेंट के रूप में सामने आया, जिसमें 14 फीसदी वृद्धि हुई। सेक्टरवार आंकड़ों में रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में 62 फीसदी की उछाल दर्ज हुई, जिसे आरबीआई ने अनिवार्य कर्ज श्रेणी में शामिल किया है। इसके अलावा, जेम्स एंड जूलरी तथा इंजीनियरिंग सेक्टर में 36 फीसदी की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई, जो इन्हें सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में शामिल करता है। कॉरपोरेट सेक्टर में कर्ज वृद्धि 12 फीसदी रही, जबकि नॉन-फूड क्रेडिट 14 फीसदी बढ़ा। अमेरिकी टैरिफ में बदलाव के कारण जनवरी में एक्सपोर्ट क्रेडिट 17.2 फीसदी घट गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में इसमें 7 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई थी। यह वैश्विक आर्थिक बदलाव का असर भारतीय क्रेडिट मार्केट पर भी दिखाई दे रहा है।

भारतीय शेयर बाजार में इस सप्ताह मिलाजुला रुझान देखा गया

सेंसेक्स और निफ्टी में साप्ता हिक आधार पर एक फीसदी से अ धिक तेजी रही

मुंबई । भारतीय शेयर बाजार ने इस सप्ताह मिश्रित रुझान दिखाया, जिसमें शुरुआती मजबूती के बाद मध्य और अंत में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। बाजार के जानकारों का कहना है कि वैश्विक बाजार के कमजोर संकेतों और बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिमों के बीच भारतीय बाजारों में स्थिरता बनी रही, निवेशकों का नजरिया तेजी से सतर्क हो गया। पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच जारी संघर्ष ने भी बाजार में अनिश्चितता पैदा कर दी है। इस तनाव की वजह से निवेशकों का भरोसा डगमगाया है। जिससे सप्ताह के ओ खिर में शेयर बाजार में एक फीसदी से अ धिक की गिरावट देखी गई। सप्ताह की शुरुआत सोमवार को हरे निशान से हुई, जब वैश्विक बाजारों में तेजी और बैंक एवं सेवा क्षेत्र में खरीदारी के चलते प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ खुले। बीएसई सेंसेक्स ने 621.78 अंकों की बढ़त के साथ 83,436.49 पर, जबकि एनएसई निफ्टी 180.05 अंकों की तेजी के साथ 25,751.30 पर कारोबार शुरू किया। दिन के अंत तक सेंसेक्स 479.95 अंक और निफ्टी 141.75 अंक ऊपर बंद हुए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने वैश्विक व्यापार की धाराओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया, जिससे निवेशकों का मनोबल बढ़ा। मंगलवार को बाजार में अचानक गिरावट देखने को मिली। एआई से जुड़े संभावित व्यवधानों और आईटी शेयरों में भारी बिकवाली के चलते सेंसेक्स 525.29 अंक गिरकर 82,769.37 पर और निफ्टी 145.85 अंक घटकर 25,567.15 पर खुला। दिन के अंत में सेंसेक्स 1,068.74 अंक और निफ्टी 288.35 अंक गिरकर सप्ताह के शुरुआती उत्साह को झटका लगा। बुधवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़ी बढ़त देखी गई, लेकिन दिन के अंत में सूचकांक केवल मामूली बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए। गुरुवार को आईटी शेयरों में खरीदारी और विदेशी फंड प्रवाह ने शुरुआती कारोबार में बाजार को बढ़त दिलाई। हालांकि, दिनभर उतार-चढ़ाव के बाद सेंसेक्स 27.46 अंक गिरकर और निफ्टी 14.05 अंक बढ़कर सपाट बंद हुए। शुक्रवार को वैश्विक बाजारों में कमजोरी और विदेशी फंडों की नई निकासी के

चलते दोनों प्रमुख सूचकांकों में गिरावट रही। सेंसेक्स 961.42 अंक गिरकर 81,287.19 पर और निफ्टी 317.90 अंक घटकर 25,178.65 पर बंद हुआ। भारतीय शेयर बाजार ने इस सप्ताह अत्यधिक अस्थिरता दिखाई। शुरुआती उत्साह के बाद मध्य सप्ताह में आईटी शेयरों और वैश्विक जोखिमों के कारण गिरावट देखी गई, जबकि सप्ताह के अंत में विदेशी फंड निकासी और वैश्विक दबाव ने बाजार को लाल निशान में बंद करवाया। निवेशकों के लिए यह सप्ताह सीखने और सतर्क रहने का रहा।

विशाल मेगा मार्ट की प्रवर्तक इकाई ने 13.96 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची

नई दिल्ली । समायत सर्विसेज एलएलपी ने खुले बाजार में दो किस्तों में 65.25 करोड़ शेयर बेचे, जो कंपनी की कुल 13.96 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर हैं। शेयरों का मूल्य 117-117.03 रुपए प्रति शेयर रहा, जिससे कुल लेनदेन मूल्य 7,635.55 करोड़ रुपए हुआ। इस बिक्री के बाद समायत सर्विसेज की विशाल मेगा मार्ट में हिस्सेदारी 54.09 फीसदी से घटकर 40.13 फीसदी रह गई। अभी भी यह सबसे बड़ा शेयरधारक है, लेकिन नियंत्रण पहले की तुलना में कम हुआ। समायत सर्विसेज एलएलपी एक विशेष-प्रयोजन इकाई है, जिसका स्वामित्व केदारा कैपिटल और पार्टनर्स ग्रुप, स्विट्जरलैंड के पास है। इस लेनदेन से निवेशकों के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं, और बाजार में स्थिर प्रतिक्रिया देखने को मिली।

अमेरिका और ईरान में जंग.....सोना 170000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 300000 लाख रुपये

मुंबई ।

इजरायल ने फिर ईरान पर हमला कर दिया है। इजरायली रक्षामंत्री ने इसकी पुष्टि कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार इजरायल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। हमले पर ईरान की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। ईरान की प्रतिक्रिया जिस तरह से सामने आई है उससे साफ है कि यह तनाव शायद ही जल्द समाप्त हो। अगर अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है, तब इसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर होगा। आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर के दाम इजाफा देखने को मिल सकता है। जानकारों का मानना है कि घरेलू बाजार में सोने का भाव 170000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी फिर से 300000 लाख रुपये के स्तर तक पहुंच सकती है। सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट बताते हैं, ÷अमेरिका-ईरान तनाव की वजह से अनिश्चितता के दौर में इजाफा होगा। निवेशक ऐसी परस्थिति में सुरक्षित निवेश की तलाश करेगा। हम सोने और चांदी की कीमतों में तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं, ÷सीओएमईएक्स गोल्ड रेट 5300 डॉलर प्रति आउंस के स्तर पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसके ऊपर जाने पर भारत में सोने का भाव 168000 रुपये प्रति 10 ग्राम से 170000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर तक जा सकता है।÷

शुक्रवार को सीओएमईएक्स सिल्वर रेट 93 डॉलर प्रति आउंस के स्तर पर बंद हुआ था। चांदी की कीमतें 95 डॉलर प्रति आउंस के स्तर पर चुनौतियों का सामना कर रही हैं। एक्सपर्ट मानते हैं, ÷अगर सीओएमईएक्स सिल्वर रेट 95 डॉलर प्रति आउंस के स्तर को क्रॉस करने

में सफल रही तब यह फिर से 100 डॉलर प्रति आउंस के स्तर तक पहुंच सकती है। भारत में चांदी की कीमतें फिर से 300000 लाख रुपये के स्तर तक जा सकता है।÷ हालिया समय में सोने और चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिली है। हालांकि, उस हिसाब से फरवरी का महीना नहीं बीता है।

गोल्ड और सिल्वर एटीएफ का एनएवी अब भारतीय बाजार की कीमत पर

-अब ईटीएफ का एनएवी ज्यादा पारदर्शी और भारतीय बाजार के अनुकूल होगा

नई दिल्ली । अभी तक गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ अपने पास रखे सोने और चांदी की कीमत तय करने के लिए एलबीएमए (लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन) की एएम फिक्सिंग का इस्तेमाल करते थे। इसके बाद कई चरणों में बदलाव किया जाता था, जैसे डॉलर से रुपये में बदलना, आयात शुल्क, कस्टम ड्यूटी, ढुलाई खर्च और अन्य टैक्स या फीस। इस वजह से निवेशकों के लिए ईटीएफ का एनएवी वास्तविक भारतीय बाजार की कीमत से थोड़ा अलग दिखाई देता था। 1 अप्रैल 2026 से यह प्रक्रिया बदल जाएगी। अब ईटीएफ ,को अपने बुलियन होल्डिंग की कीमत तय करने के लिए भारतीय एक्सचेंजों द्वारा जारी डॉमेस्टिक स्पॉट प्राइस का उपयोग करना होगा। ये वही कीमतें हैं जिन पर एमसीएक्स और एनएसई पर फिजिकल सोना-चांदी के सौदे होते हैं। इसका मतलब एनएवी सीधे भारत के बाजार की वास्तविक कीमत को दिखाएगा। इस बदलाव से ईटीएफ का एनएवी ज्यादा पारदर्शी और भारतीय बाजार के अनुकूल होगा। डॉलर-रुपये के बदलाव या अतिरिक्त शुल्क जोड़ने की जरूरत खत्म हो जाएगी। निवेशकों के लिए सुरक्षा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस रोज़ाना की कीमतें अब भारत के फिजिकल मार्केट के हिसाब से तय होंगी।

सरकार ने फोर्टिफाइड चावल वितरण अस्थायी रूप से रोका

लंबे समय तक गोदाम में रखने पर आ रही पोषक तत्वों में कमी

नई दिल्ली। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय) और अन्य योजनाओं के तहत मिलने वाले फोर्टिफाइड चावल में पोषक तत्व मिलाने की प्रक्रिया अस्थायी रूप से रोक दी है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार लंबे समय तक गोदामों में रखने से चावल में जो विटामिन और मिनरल्स मिलाए जाते हैं, उनमें कमी आ रही थी। सरकार ने आईआईटी खड़गपुर को यह अध्ययन करने का काम सौंपा था कि अलग-अलग मौसम और वातावरण में चावल कितने समय तक सुरक्षित रहता है। रिपोर्ट में पाया गया कि चावल रखने का स्थान, तापमान, हवा में नमी और पैकिंग सामग्री फोर्टिफाइड चावल की गुणवत्ता पर बड़ा असर डालते हैं। लंबे समय तक भंडारण और बार-बार परिवहन से पोषक तत्व जल्दी घट जाते हैं और चावल जल्दी खराब होने लगता है। राशन का चावल अक्सर 2-3 साल तक सरकारी गोदामों में रखा जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए सालाना 372 लाख टन चावल की जरूरत होती है। जबकि सरकारी भंडार में कुल उपलब्धता लगभग 674 लाख टन है, जिसमें 2025-26 की खरीफ फसल भी शामिल है। खाद्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पोषक तत्व मिलाने की प्रक्रिया रोकने से राशन की मात्रा या स्कूलों और आंगनवाड़ी में मिलने वाले मध्याह्न भोजन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

सम्पादकीय

"मानवता सुख शांति प्रेम का, अखिल विश्व में हो
विस्तारस्वतंत्रता का हनन न होवे, रहे सुरक्षित जन अधिकार"

भाईचारा ही लोकतंत्र की असली ताकत

भारत में लोकतंत्र की परंपरा बहुत मजबूत रही है और यहां नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार संविधान के तहत मिला हुआ है। मगर इसके साथ ही कुछ जिम्मेदारियां भी अभिन्न हैं, जो आपस में मिल कर ही देश में सद्भाव और सहयोग पर आधारित समाज को जीवन देती हैं। विडंबना यह है कि कई बार अभिव्यक्ति की आजादी पर पूर्वाग्रह और महज धारणा पर आधारित राय हावी दिखती है और इसे किसी व्यक्ति या समुदाय को कठघरे में खड़ा करने का औजार बना लिया जाता है। अपनी प्रभावी संप्रेषण शक्ति और लोगों तक व्यापक पहुंच रखने वाले कला माध्यम के रूप में फिल्मों में अभिव्यक्ति के रचनात्मक पक्ष का इस्तेमाल करते हुए बड़े से बड़े प्रश्नों पर विचार किया जाता रहा है और इसे सभी स्तरों पर स्वीकार्यता भी मिलती रही है। मगर अफसोस की बात यह भी है कि इसी सुविधा का कई बार गलत फायदा भी उठाया जाता है। अभिव्यक्ति के नाम पर किसी फिल्म में परोसी गई कहानी के जरिए किसी समुदाय के बारे में गलत धारणा बनाने की कोशिश की जाती है। इसी तरह, कुछ नेता भी अपनी जिम्मेदारियों और सीमाओं को ताक पर रख कर बेहिचक ऐसे बयान देते हैं, जिससे अलग-अलग समुदायों के बीच द्वेष पैदा होता है। जबकि इसका नतीजा इस रूप में भी सामने आ सकता है कि अलग-अलग समुदायों के बीच सद्भावना आधारित संवाद या संबंध पीछे छूट जाए। जाहिर है, देश को इसके दूरगामी नुकसान हो सकते हैं। शायद यही वजह है कि हाल ही में अपने शीर्षक की वजह से विवाद के घेरे में आई एक फिल्म पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव के लिए भाईचारा जरूरी है। इस मामले में न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने अपने अलग फैसले में कहा कि सरकारी और गैरसरकारी सहित किसी भी जानी-मानी हस्ती और खासतौर पर ऊंचे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए भाषण, मीम, कार्टून या दृश्य माध्यमों के जरिए किसी भी समुदाय को बदनाम करना, उस पर धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर निशाना साधना संविधान का उल्लंघन है। दरअसल, पिछले कुछ समय से देश भर में अलग-अलग संदर्भ में कुछ नेताओं के बयानों या फिल्मों ने कई बार विवाद की स्थिति खड़ी कर दी। सार्वजनिक रूप से वैसी बातें करने में भी संकोच नहीं किया गया, जिसका कोई मजबूत आधार नहीं था, लेकिन उसने जन मानस के बीच राय बनाने में भूमिका निभाई। वे फिल्मों में चित्रित ब्योरे हों या किसी नेता का बयान, ऐसे अनेक मौके सामने आए, जब उसकी वजह से नाहक विवाद खड़ा हुआ, आपसी सद्भाव को नुकसान पहुंचा और यहां तक कि कोई खास समुदाय अपने आपको कठघरे में खड़ा या असुरक्षित महसूस करने लगा। सवाल है कि किसी व्यक्ति या समुदाय को लक्ष्य कर बोलने की आजादी के तहत जो भी कहा जाता है, क्या कभी उसके आधार और असर को लेकर भी विचार करने की कोशिश की जाती है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि सद्भावना और आपसी भाईचारा देश के संविधान के बुनियादी उद्देश्यों में से एक है। अनुच्छेद 51ए(ई) के तहत हर नागरिक का यह बुनियादी कर्तव्य है कि वह धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं की सीमा से अलग होकर नागरिकों के बीच सद्भावना और सहयोग को बढ़ावा दे। मगर धर्म, भाषा, जाति या क्षेत्र के आधार पर अगर किसी व्यक्ति या समुदाय को निशाना बनाया जाता है, तो यह संविधान और मानवीय मूल्यों का विरुद्ध है।

लोकतंत्र में न्यायपालिका की गरिमा सर्वोपरि

गोपाल कृष्ण व्यास
पूर्व न्यायाधीश

भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र है। यहाँ शासन व्यवस्था तीन प्रमुख स्तंभों—न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका—पर आधारित है। इन तीनों के बीच संतुलन और परस्पर सम्मान ही लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाता है। यदि इनमें से कोई एक स्तंभ कमजोर होता है, तो लोकतांत्रिक ढांचा प्रभावित हो सकता है।

न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक माना गया है। उसका दायित्व केवल कानून की व्याख्या करना ही नहीं, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना भी है। जब शासन-प्रशासन में किसी प्रकार की त्रुटि, अतिरेक या मनमानी दिखाई देती है, तब न्यायपालिका हस्तक्षेप कर संतुलन स्थापित करती है। यही कारण है कि उसे लोकतंत्र का अंतिम प्रहरी कहा जाता है। हाल के समय में न्यायपालिका के आदेशों की अवहेलना करना, अथवा मीडिया के माध्यम से उसकी गरिमा को आहत करने का प्रयास करना एक चिंताजनक प्रवृत्ति के रूप में सामने आया है। न्यायालयों की आलोचना लोकतांत्रिक अधिकार है, किंतु वह मर्यादित और तथ्यपरक होनी चाहिए। निराधार आरोप या अपमानजनक टिप्पणियाँ न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता को प्रभावित करती हैं।

इसी संदर्भ में माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा एन सी ई आर टी के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। न्यायालय यदि यह अनुभव करे कि किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है, तो विधि सम्मत कार्रवाई करना उसका अधिकार और कर्तव्य दोनों है। यह भी आवश्यक है कि न्यायपालिका अपनी निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से संतुलित दूरी रखे। संविधान निर्माताओं ने शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत इसी उद्देश्य से स्थापित किया था, ताकि कोई भी अंग निरंकुश न बन सके और लोकतंत्र सुरक्षित रहे।

भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में न्यायपालिका की साख और गरिमा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि न्यायालयों के आदेशों का सम्मान नहीं होगा, तो कानून का शासन कमजोर पड़ेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। अत: सभी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों का यह दायित्व है कि वे न्यायपालिका के निर्णयों का सम्मान करें और असहमति भी संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर व्यक्त करें। लोकतंत्र की मजबूती के लिए तीनों स्तंभों के बीच संतुलन, पारदर्शिता और परस्पर सम्मान अनिवार्य है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना केवल न्यायालयों का ही नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का सामूहिक दायित्व है।

लोकतंत्र में भरोसा बढ़ाने वाला निर्णय

सुप्रीम कोर्ट का मतदाता सूची पर ऐतिहासिक आदेश

प्रो. हरबंश दीक्षित

गत शुक्रवार को देश एक अभूतपूर्व अदालती निर्णय का साक्षी बना। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में मतदाता सूची से जुड़े विवादित दावों को निपटाने के लिए न्यायिक अधिकारियों की मदद लेने का ऐतिहासिक आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच जारी गतिरोध को देखते हुए यह फैसला सुनाया। बाद में उसने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ती है, तो ओडिशा और झारखंड के न्यायिक अधिकारियों को बंगाल में मतदाता सूची से संबंधित दावों और आपत्तियों को तय करने के लिए लगाया जा सकता है। यह हस्तक्षेप केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया को गति देने का उपाय नहीं, बल्कि लोकतंत्र के उस मूल आत्मा की रक्षा का संवैधानिक संकल्प है, जिसका आधार प्रत्येक नागरिक का निर्बाध और सुरक्षित मताधिकार है। जब मतदाता सूची जैसे मूल दस्तावेज की शुचिता पर प्रश्न उठ खड़े हों और लाखों नागरिकों की लोकतांत्रिक पहचान पर संशय हो, तब न्यायपालिका का यह हस्तक्षेप लोकतंत्र की विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित करने का एक निर्णायक प्रयास बन जाता है। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति चुनाव में नहीं, बल्कि उस विश्वास में निहित होती है, जिसके साथ नागरिक चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यह विश्वास मतदाता सूची से प्रारंभ होता है। मतदाता सूची केवल नामों का संकलन नहीं, बल्कि नागरिक की संवैधानिक पहचान का प्रमाण है। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम इस सूची से अनुपस्थित हो जाता है, तो वह अपने मताधिकार से वंचित हो जाता है और यदि अपात्र व्यक्ति इसमें सम्मिलित हो जाता है तो वह चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करता है। इसीलिए मतदाता सूची की शुचिता, लोकतंत्र की वैधता का आधार है।

सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मी चरण सेन बनाम एकेएम हसन (1985) के ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया था कि मतदाता सूची की शुद्धता चुनाव की वैधता की आधारशिला है और इसे सुनिश्चित करना लोकतांत्रिक व्यवस्था की अनिवार्य शर्त है। न्यायालय ने इस पर बल दिया कि मतदाता सूची में त्रुटियां केवल प्रशासनिक चूक नहीं होतीं, बल्कि वे लोकतंत्र की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती हैं। बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के दौरान लगभग 45 लाख विवादित मतदाता दावों का

लंबित होना इसी संवेदनशील प्रश्न की गंभीरता को दर्शाता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार प्रदान करता है, जो लोकतंत्र में उसकी संप्रभुता की अभिव्यक्ति है। वहीं अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की व्यापक शक्ति देता है, ताकि चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष बनी रहे। हालांकि इन संवैधानिक प्रविधानों की वास्तविक प्रभावशीलता तभी संभव है, जब मतदाता सूची पूर्णत: शुद्ध, अद्यतन और विश्वसनीय हो। यदि इस आधार में ही त्रुटि हो, तो लोकतंत्र की संपूर्ण संरचना प्रभावित होती है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 142 के अंतर्गत उसकी संवैधानिक शक्तियों का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। अनुच्छेद 32 नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 142 न्यायालय को %पूर्ण न्याय% सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इन प्रविधानों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए असाधारण कदम उठाना आवश्यक हो, तब न्यायपालिका प्रभावी और निर्णायक भूमिका निभा सके। न्यायिक अधिकारियों की सहायता सुनिश्चित करने का निर्णय इसी संवैधानिक दायित्व का प्रकटीकरण है। इस हस्तक्षेप का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इससे मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया को प्रशासनिक विवेक से ऊपर उठाकर न्यायिक विश्वसनीयता प्रदान की गई है। न्यायिक अधिकारी अपनी विधिक समझ के कारण इस प्रकार के संवेदनशील कार्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं।

यह घटनाक्रम भारतीय संविधान की संस्थागत परिपक्वता का भी सशक्त उदाहरण है। निर्वाचन आयोग, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने-अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए लोकतंत्र की रक्षा के लिए समन्वित भूमिका निभाई है। यह उस संवैधानिक संतुलन का प्रमाण है, जिसमें संस्थाएं केवल अपने अधिकार क्षेत्र तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि राष्ट्रहित और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाती हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक अधिकारियों की छुट्टियां रद करना भी इसी संवैधानिक प्राथमिकता का प्रतीक है। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि जब लोकतंत्र की मूल प्रक्रिया की शुचिता का प्रश्न हो, तब संस्थागत सुविधा नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्व सर्वोपरि होता है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय एक व्यापक और दूरगामी संदेश यह भी देता है कि भारत में लोकतंत्र केवल एक औपचारिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक संरक्षित संवैधानिक मूल्य है, जिसकी रक्षा के लिए संविधान और उसकी संस्थाएं सदैव सजग हैं। यह हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव प्रक्रिया का प्रत्येक चरण संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हो। मतदाता सूची की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप भारतीय लोकतंत्र की शक्ति, संवैधानिक प्रतिबद्धता और संस्थागत सजगता का भी सशक्त प्रमाण है। अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि लोकतंत्र की आधारशिला यानी मताधिकार को किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। असाधारण परिस्थितियों में लिया गया यह असाधारण निर्णय न केवल मतदाता सूची की विश्वसनीयता को सुदृढ़ करेगा, बल्कि नागरिकों के उस विश्वास को भी और मजबूत करेगा, जो लोकतंत्र की वास्तविक और स्थायी शक्ति है। यही विश्वास भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है और उसकी रक्षा ही संविधान की सर्वोच्च प्रतिबद्धता है।

आसान नहीं व्यापार समझौतों का लाभ लेना

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

पिछले कुछ सालों में भारत मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से कई देशों से मुक्त व्यापार की राह पर आगे बढ़ा है। इससे भारतीय वस्तुओं के लिए दुनिया के बाजारों में निर्यात पहुंच बढ़ी है। गत दिवस पीएम मोदी ने कहा कि इजरायल के साथ भी भारत का एफटीए जल्दी ही आकार लेते हुए दिखाई देगा और भारत जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यस्था वाला देश होगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अवैध ठहराए जाने के बाद 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए भारत समेत सभी देशों पर 15 प्रतिशत अस्थाई ग्लोबल टैरिफ लागू हो गया है। इस अवधि के बाद अमेरिकी संसद तय करेगी कि इसे आगे बनाए रखना है या नहीं अभी अमेरिकी प्रशासन के पास टैरिफ लगाने की कई शक्तियां बची हुई हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी संसद से टैरिफ पर प्रस्ताव मंजूर होने के बाद भारत के साथ किया गया व्यापार समझौता अपने पूर्व निर्धारित रूप में ही लागू होगा। ऐसे में जहां आगामी 150 दिन टैरिफ की अस्थाई कमी निर्यात बढ़ाने के लिए हितकर है, वहीं इसके बाद दोनों देशों के बीच अंतरिम व्यापार समझौता अमेरिका को निर्यात बढ़ाने के लिए लाभप्रद होगा। भारत के लिए अमेरिका एक सबसे बड़ा बाजार है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और अमेरिका के बीच 131.84 अरब डालर मूल्य का व्यापार हुआ। इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल से दिसंबर के बीच भारत ने अमेरिका को 65.88 अरब डालर मूल्य का निर्यात किया है। ऐसे में अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौता भारतीय निर्यात बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। अमेरिका द्वारा शुरू किए गए टैरिफ और व्यापार व्यवधानों ने भारत को वैकल्पिक बाजार खोजने और नए व्यापार गठबंधन बनाने की राह पर आगे बढ़ाया है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत ने पिछले वर्ष कई व्यापार समझौते किए हैं और इस वर्ष भी कई नए व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन की तैयारी है। इनमें अत्यधिक महत्वपूर्ण यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ मुक्त व्यापार समझौता भी शामिल है। हाल में एआइ समिट के दौरान ईयू के कई राष्ट्राध्यक्षों ने 27 जनवरी को भारत-ईयू के दौरान किए गए एफटीए को शीघ्र कार्यान्वित किए जाने के लिए समर्थन दिया। यह एफटीए दुनिया की

> व्यापार समझौतों से देश को आर्थिक शक्ति बनाने के लिए अधिकारियों को नए दौर की जरूरत के मुताबिक शिक्षित-प्रशिक्षित करने के साथ सरकारी और निजी क्षेत्रों में शोध, विकास एवं नवाचार बढ़ाना होगा।

दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का बेजोड़ उदाहरण है। इस समझौते को सभी व्यापार समझौतों की जननी कहा गया है। इस एफटीए से दो अरब लोगों का एक साझा बाजार तैयार होगा, जिसका संयुक्त बाजार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग एक चौथाई हिस्से के बराबर होगा। अनुमान है कि यह एफटीए आगामी छह महीने में कार्यान्वित होते हुए दिखाई देगा। पिछले वर्ष भारत द्वारा ब्रिटेन, ओमान के साथ किए गए एफटीए इसी अप्रैल से और न्यूजीलैंड के साथ किया गया एफटीए सितंबर से कार्यान्वित होते हुए दिखाई देगा। इन सबके साथ-साथ मारीशस, संयुक्त अरब अमीरात, आस्ट्रेलिया और चार यूरोपीय देशों के समूह यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (एफ्टा) के साथ हुए एफटीए से भी इस वर्ष निर्यात बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस वर्ष पेरू,चिली, आसियान, मैक्सिको, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इजराइल, भारत गल्फ कंट्रीज काउंसिल सहित अन्य प्रमुख देशों के साथ भी नए एफटीए हो सकते हैं। इस तरह निर्यात बढ़ने की संभावनाओं का यह एक अनुकूल परिदृश्य है, लेकिन ट्रंप प्रशासन के लगातार बदलते रवैये को देखते हुए भारत के लिए उचित यही होगा कि वह अन्य देशों से व्यापार समझौते संबंधी वार्ताओं को गति दे।

वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत से निर्यात बढ़ाना कोई सरल काम नहीं है। भारत को निर्यात की नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। एक फरवरी को वित्त मंत्री की ओर से प्रस्तुत केंद्रीय बजट में विनिर्माण, वस्त्र, चमड़ा और समुद्री भोजन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए निर्यात बढ़ाने के लिए जो कई रणनीतिक उपाय किए गए हैं, उन पर नए वित्तीय वर्ष में शुरुआत से ही ध्यान देना होगा। निर्यात बढ़ाने के लिए हमें उत्पादों की गुणवत्ता और नए सुधारों पर भी ध्यान देना होगा। व्यापार समझौते अभी ऐतिहासिक कागजी दस्तावेज हैं। इनका पूरा लाभ तभी मिलेगा, जब भारत नई पीढ़ी के सुधारों और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को आगे बढ़ाएगा। नए व्यापार समझौतों से भारत दुनिया की बड़ी-बड़ी मंडियों में प्रवेश पाने में सफल तो होगा, लेकिन देश को व्यापारिक महाशक्ति बनाने के लिए आकर्षक दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाला माल तैयार करना होगा। सिस्टमैटिक्स ग्रुप की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत द्वारा व्यापार समझौतों का अधिकतम लाभ लेने के लिए सबसे पहले किफायती लागत पर गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, लाजिस्टिक्स और कस्टम प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे सुधारों पर तेजी से आगे बढ़ना होगा। निर्यातकों की दिक्कतें केवल शुल्क वृद्धि तक सीमित नहीं हैं।

वे एंटी-डंपिंग शुल्क से भी संबंधित हैं। घरेलू कच्चे माल की ऊंची लागत और ईंधन की उच्च कीमतों के कारण भी भारत की ओर से निर्यात किए जाने वाले उत्पाद वैश्विक स्तर से करीब 20 फीसदी की अधिक लागत पर दिखाई देते हैं। व्यापार समझौतों से देश को आर्थिक शक्ति बनाने के लिए अधिकारियों को नए दौर की जरूरत के मुताबिक शिक्षित-प्रशिक्षित करने के साथ सरकारी और निजी क्षेत्रों में शोध, विकास एवं नवाचार बढ़ाना होगा।

जीवन धारा

आप खुद एक पुस्तकालय हैं

वृद्धावस्था जीवन का अंत नहीं, बल्कि हमारे संपूर्ण अस्तित्व का निचोड़

एरिक एरिक्सन

मानव जीवन विकास के विभिन्न क्रमिक चरणों से गुजरता है, जिसमें अंतिम चरण सबसे चुनौतीपूर्ण होने के साथ-साथ आध्यात्मिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण भी है। इसीलिए, मैं मानता हूं कि वृद्धावस्था जीवन का अंत नहीं, बल्कि हमारे संपूर्ण अस्तित्व का निचोड़ है। जब हम उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचते हैं, तो हमें अपने अतीत को टुकड़ों में देखने के बजाय एक विस्तृत और पूर्ण तस्वीर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जीवन के उतार-चढ़ाव, सफलताएं और असफलताएं-इन सबका समग्र रूप से स्वागत करना ही समय पर प्राप्त की गई असली जीत है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जब अपनी जीवन-यात्रा के प्रति 'कृतज्ञता' महसूस करता है, तो उसके भीतर एक ऐसी गहन शांति का संचार होता है, जो उतावलेपन से भरे युवाओं के लिए दुर्लभ है। इस अवस्था की सबसे अनमोल देन बुद्धिमानी है। यह वह अद्वितीय गुण है, जो केवल समय की मार, सफेद बालों और चेहरे की झुर्रियों के अनुभव से ही निखरता है। यह वह आंतरिक शक्ति है, जो मृत्यु की अपरिहार्यता के सामने भी जीवन की गरिमा और उसके अर्थ को अक्षुण्ण बनाए रखती है। अत:, वरिष्ठ नागरिकों को स्वयं को समाज पर भार समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत, उन्हें खुद को उस जीवंत 'पुस्तकालय' के रूप में देखना चाहिए, जहां हर समस्या और मानवीय भावना से जुड़ी अनुभवी सलाह उपलब्ध है। इस उम्र में प्रेरणा का सबसे अक्षय स्रोत 'जेनेरेटिविटी' है, जिसका अर्थ है अपनी संचित विरासत और ज्ञान को अगली पीढ़ी के हाथों में सौंपना। जो बुजुर्ग अपने संघर्षों और सीखों को युवाओं के साथ साझा करते हैं, वे मानसिक रूप से कभी वृद्ध नहीं होते, बल्कि उनका अस्तित्व तो आने वाली पीढ़ियों के मार्ग को आलोकित करने वाला एक शाश्वत दीपक बन जाता है। इसलिए, वृद्धावस्था आत्म-ग्लानि में डूबने का नहीं, बल्कि स्वयं से यह कहने का समय है कि 'मैंने अपना जीवन जिया है और इसका हर पल सार्थक था।'

> वरिष्ठ नागरिकों को खुद को उस जीवंत 'पुस्तकालय' के रूप में देखना चाहिए, जहां हर समस्या और मानवीय भावना से जुड़ी अनुभवी सलाह उपलब्ध है। जो बुजुर्ग अपने संघर्षों और सीखों को युवाओं के साथ साझा करते हैं, वे मानसिक रूप से कभी वृद्ध नहीं होते।

सरस्वती सिंधु सभ्यता: भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है राखीगढ़ी का पुरास्थल

भारत के प्राचीन इतिहास के प्रति वर्तमान सरकार का झुकाव कोई अचंभित करने वाला विषय नहीं है। इसी कड़ी में आगामी वित्त वर्ष का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री महोदया ने 15 पुरातात्विक स्थलों को उत्खनित व विकसित करने हेतु विशेष राशि आवंटित की है। इन पुरास्थलों में राखीगढ़ी, लोथल, धोलावीरा, आदिचिन्नलूर आदि प्रमुख हैं। इन सभी पुरास्थलों में से एक राखीगढ़ी के लिए विशेष तौर पर 500 करोड़ की राशि आवंटित की गई है । राखीगढ़ी की ऐसी क्या महत्वता है जो सरकार का झुकाव इस ओर अधिक है । राखीगढ़ी हरियाणा के हांसी जिले में अवस्थित है। भारत की प्राचीनतम सरस्वती सिंधु सभ्यता का यह पुरास्थल ऋग्वेद में वर्णित दृष्दवति नदी के किनारे पर स्थित था। इस पुरास्थल की 1997 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा समय समय पर खुदाई की गई है।

हाल ही में हुए सघन पुरातात्विक सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ है की राखीगढ़ी नगर का कुल क्षेत्रफल 350 हेक्टेयर से अधिक था। यह विस्तार राखीगढ़ी को सरस्वती सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर होना सिद्ध करता है। यहां यह बात भी उल्लेखनीय है कि राखीगढ़ी से कुछ दूरी पर ही सरस्वती नदी व दृष्दवति नदी ता संगम अवस्थित था। यही कारण है की सभ्यता का सबसे बड़ा नगर यहां स्थित था । राखीगढ़ी का पुरास्थल कुल 11 टीलों में विभाजित है। यहां हुए पुरातात्विक उत्खननों के फलस्वरूप सरस्वती सिंधु सभ्यता के प्रारंभिक व विकसित काल के पुरावशेष प्रकाश में आए हैं। यहां से प्राप्त वैज्ञानिक तिथियों के अनुसार वर्तमान समय ले 8000 वर्ष पूर्व से लेकर 4000 वर्ष पूर्व तक यहां मानव बसाहट विद्यमान थी । सरस्वती सिंधु सभ्यता के परवर्ती काल के पुरावशेष हमें राखीगढ़ी से प्राप्त नहीं होते । राखीगढ़ी से मिलने वाले पुरावशेष भारतीय इतिहास में रचे गए आर्य आगमन के कुचक्र को धराशायी करने में सहायक सिद्ध होते हैं।

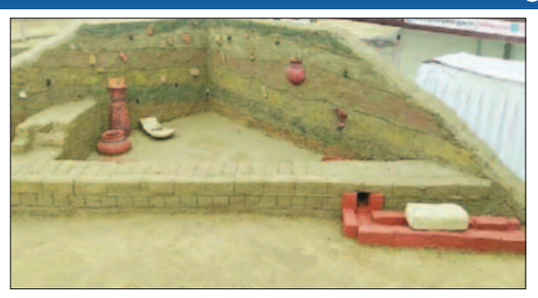

यहां हुए पुरातात्विक उत्खनन में उत्खननकर्ता डॉ अमरेन्द्र नाथ को विभिन्न आकार कि यज्ञवेदियां प्राप्त हुईं थी। यह यज्ञोवेदियां योनी व चित्ती आकार कि हैं जो सरस्वती सिंधु सभ्यता के विकसित काल के दौरान की हैं । यह इस बात की द्योतक हैं कि राखीगढ़ी में रहने वाले लोग वर्तमान समय से 4500 वर्ष पूर्व वैदिक परंपराओं का अनुसरण करते थे। यहां इस तथ्य का उल्लेख भी आवश्यक है कि ऋग्वेद में दृष्दवती नदी के किनारे रहने व यज्ञ संपादित करने की उल्लेख आता है । इस प्रकार राखीगढ़ी के उपरोक्त पुरातात्विक साक्ष्य ऋग्वेद के विवरणों से साम्यता रखते हैं । इस आधार पर वैदिक जनों का 1500 ईसा पूर्व बाहर से आने के मत पर भी प्रश्नचिन्ह खड़े होते हैं । राखीगढ़ी की महत्वता इस वैज्ञानिक तथ्य में भी निहित है कि यहां मौजूद सरस्वती सिंधु सभ्यता के कंकालों के डीएनए अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि इन कंकालों में कोई मध्य एशियाई जीन मौजूद नहीं था । इस प्रकार जिन विद्वानों का यह मत था कि संभवत: सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग बाहरी थे इस पर पूर्ण विराम लग गया है तथा यह सभ्यता पूर्णत: स्वदेशी सभ्यता थी । आर्य आगमन के मिथक को सिद्ध करने के लिए सरस्वती सिंधु सभ्यता में घोड़े की अनुपस्थिति का मुद्दा उठाया जाता है। परन्तु राखीगढ़ी में हुए पुरातात्विक उत्खनन से घोड़े की मृण्मूर्ति प्रकाश में आई है। उत्खननकर्ता डॉ अमरेन्द्र नाथ ने अपने शोध पत्र में इस विषय का उल्लेख किया है । यह इस बात की द्योतक है कि इस सभ्यता में घोड़ा पहले से ही विद्यमान था ।

राखीगढ़ी उत्खनन

राखीगढ़ी उत्खनन से विभिन्न अर्ध कीमती पत्थर जैसे कार्नेलियन, अगेट, जैस्पर, लाजवर्द आदि के मनके प्राप्त होते हैं । यह पत्थर गुजरात व अफगानिस्तान से यहां लाए जाते थे। यह पुरावशेष इस बात को प्रमाणित करते हैं की यहां रहने वाले लोग दूरस्थ इलाकों तक व्यापार करते रहे होंगे। राखीगढ़ी में इन अर्ध कीमती पत्थरों का उपयोग कर मनके व आभूषण भी बनाए जाते थे । यहां ये तांबे की छेनियां भी प्राप्त हुई हैं, गौरतलब है कि तांबे की खदाने राखीगढ़ी के आसपास विद्यमान नहीं हैं। वर्ष 2023-24 में डॉ संजय मंजुल के नेतृत्व में हुए पुरातात्विक उत्खनन में राखीगढ़ी में एक स्टेडियम के होने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं । सरस्वती सिंधु सभ्यता में इसके पूर्व केवल गुजरात स्थित धोलावीरा से ही स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं ।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक शिल्पी सिंघल द्वारा सांई प्रिंटिंग डी-85, सैक्टर-7 नोएडा (गौतमबुद्धनगर) उत्तर प्रदेश से मुद्रित कराकर बी-137, न्यू अशोक नगर दिल्ली- 110096 से प्रकाशित किया। संपादक शिल्पी सिंघल, मोबाईल नंबर: 9810400661
फोन न. 0120-4129662, 9311450661। किसी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय में ही होगा। Email id - manasvivani@gmail-com. www.manasvivani.com

संक्षिप्त समाचार

स्पेसएक्स क्रू-11 की समय से पहले वापसी

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने स्पेसएक्स के क्रू-11 मिशन की समय से पहले वापसी को लेकर जानकारी दी है। अंतरिक्ष यात्री माइक फिंके ने बताया कि 7 जनवरी को अंतरिक्ष स्टेशन पर उन्हें स्वास्थ्य समस्या हुई, इसके बाद सभी चार सदस्यों को निर्धारित समय से पहले लौटाने का फैसला किया। नासा के अनुसार यह आपात स्थिति नहीं थी, बल्कि उन्नत मेडिकल जांच के लिए कदम था। क्रू-11 का कैप्सूल 15 जनवरी को सैन डिएगो तट के पास सुरक्षित उतरा और साढ़े पांच माह का मिशन पूरा हुआ।

पेंटागन ने ज्वाइंट स्टाफ निदेशक पद से वाइस एडमिरल को हटाया

पेंटागन, एजेंसी। पेंटागन ने अमेरिकी नौसेना के वाइस एडमिरल फ्रेड कैचर को ज्वाइंट स्टाफ के निदेशक पद से हटा दिया है। कैचर ने दिसंबर में ही यह पद संभाला था। प्रवक्ता ने पुष्टि की कि काचर अब अमेरिकी नौसेना में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे, लेकिन हटाने का कारण नहीं बताया। सूत्रों के अनुसार वे इस पद के लिए उपयुक्त नहीं माने गए, हालांकि किसी विशेष वजह का खुलासा नहीं हुआ। डेन केन ने उनके योगदान की सराहना की। कैचर इससे पहले जापान स्थित अमेरिकी सातवें बेड़े के कमांडर और यूएस नेवल अकादमी के प्रमुख रह चुके हैं।

अमेरिका : रिटायर्ड पायलट ने चीन में दी ट्रेनिंग, गिरफ्तार

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर पूर्व अमेरिकी वायु सेना के एलीट फाइटर पायलट और एफ-35 प्रशिक्षक गेराल्ड एडी ब्राउन जूनियर को चीनी सैन्य पायलटों को गुप्त रूप से लड़ाकू प्रशिक्षण देने के गंभीर आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल जॉन ए आइजेनबर्ग ने कहा, अमेरिकी वायु सेना ने मेजर ब्राउन को एक विशिष्ट लड़ाकू पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया था और राष्ट्र की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी। एजेंसी 2023 में ब्राउन ने चीन जाकर दिया प्रशिक्षण...ब्राउन के सैन्य करियर में संवेदनशील इकाइयों का नेतृत्व, युद्ध अभियानों का संचालन और एफ-4, एफ-15, एफ-16, ए-10 तथा एफ-35 जैसे विमानों पर लड़ाकू पायलट एवं सिम्युलेटर प्रशिक्षक के रूप में सेवा शामिल थी।

हांगकांग कोर्ट ने जिमी लाई की धोखाधड़ी में मिली सजा रद्द की

विक्टोरिया, एजेंसी। हागकांग की अपीलीय अदालत ने पूर्व मीडिया कारोबारी जिमी लाई को राहत देते हुए उनकी धोखाधड़ी मामले में सजा रद्द कर दी। 78 वर्षीय लाई ने बंद हो चुके अखबार एपल डेली की स्थापना की थी और वे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखर आलोचक रहे हैं। हालांकि, उन्हें हाल ही में चीन की ओर से लागू राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत एक अन्य मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई है, इसलिए वे जेल में ही रहेंगे।

आईएमएफ ने कहा- अमेरिकी अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत

वाशिंगटन, एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय मॉन्ट्रियल फंड ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बताते हुए कहा कि 2026 में वृद्धि दर बढ़कर 2.4 फीसदी तक पहुंच सकती है, जो 2025 के 2.2 फीसदी से अधिक होगी। आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ने कहा कि बेरोजगारी दर 4.5 फीसदी से घटकर 4.1 फीसदी हो सकती है और महंगाई 2027 तक फेडरल रिजर्व के दो फीसदी लक्ष्य तक आ सकती है।

सूडान के दारफुर में हिंसा

दारफुर , एजेंसी। सूडान के दारफुर क्षेत्र में अर्धसैनिक बलों के हमलों के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। डॉक्टरों के एक समूह के अनुसार, हालिया हमलों में कम से कम 28 लोगों की मौत हुई और 39 घायल हुए। तीन हजार से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए हैं। ज्यादातर विस्थापित महिलाएं और गर्भवती महिलाएं हैं, जिनके पास न भोजन है न ही आश्रय।

कोलंबिया यूनिवर्सिटी की छात्रा की गिरफ्तारी

न्यूयॉर्क , एजेंसी। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की छात्रा एली आघायेवा को इमिग्रेशन अधिकारियों ने हिरासत में लिया। अधिकारियों ने अपार्टमेंट में प्रवेश के लिए 'लापता व्यक्ति' की तलाश का बहाना बनाया। छात्रा के वकीलों का दावा है कि बिना वारंट गिरफ्तारी की गई। बाद में न्यूयॉर्क के मेयर ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप से बात के बाद छात्रा को रिहा करने पर सहमति बनी। यह मामला अमेरिका में सख्त हो रही इमिग्रेशन नीति पर नई बहस छेड़ रहा है।

आरोप- बांग्लादेश सरकार ने डिफाल्टर को सेंट्रल बैंक गवर्नर बनाया

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश में सेंट्रल बैंक के नए गवर्नर की नियुक्ति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि तारिक रहमान की सरकार ने एक डिफाल्टर को कारोबारी को सेंट्रल बैंक गवर्नर बना दिया है, जो देश में भीड़तंत्र की शुरुआत जैसा है। बांग्लादेश बैंक के नए गवर्नर के रूप में मोस्ताकुर रहमान की नियुक्ति के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया। जमात ए इस्लामी के प्रमुख और विपक्ष के नेता शफीकुर रहमान ने कहा कि यह फैसला पीएम की शह पर लिया गया है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इससे पहले सरकार ने अहसान हबीब मंसूर का कार्यकाल अचानक खत्म कर दिया था, जिन्हें मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने नियुक्त किया था। मंसूर ने कहा कि उन्होंने न इस्तीफा दिया और न ही उन्हें हटाए जाने की कोई आधिकारिक सूचना मिली। उन्हें यह खबर मीडिया के जरिए पता चली।

गारमेंट कारोबारी रहे हैं मोस्ताकुर रहमान : मोस्ताकुर रहमान की नियुक्ति इसलिए अलग मानी जा रही है क्योंकि अब तक बांग्लादेश में केंद्रीय बैंक का गवर्नर आमतौर पर अनुभवी बैंकर, अर्थशास्त्री या वरिष्ठ सिविल सेवक होते रहे हैं। मोस्ताकुर एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और गारमेंट कारोबारी हैं। वे हेरा स्वेटर्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और

विपक्ष बोला- ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, देश में भीड़तंत्र चल रहा

हालिया चुनाव में तारिक रहमान की बीएनपी पार्टी की केंद्रीय चुनाव संचालन समिति से भी जुड़े रहे थे। उनकी नियुक्ति को लेकर कर्ज चुकाने से जुड़े पुराने मामलों पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीडी न्यूज24 की रिपोर्ट में कहा गया कि उनकी कंपनी 86 करोड़ टका का कर्ज समय पर नहीं चुका पाई थी। एक बैंक अधिकारी ने कहा कि जो इंसान अपनी ही कंपनी के लिए स्पेशल कंडीशन पर कर्ज का पुनर्गठन कराता है, वह देश के बैंकिंग सिस्टम के हितों की रक्षा कैसे करेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका के पूर्व प्रोफेसर दीन इस्लाम ने भी कहा कि किसी एक्टिव कारोबारी को केंद्रीय बैंक का गवर्नर बनाना गलत संदेश देता है और इससे हितों के टकराव की आशंका बढ़ती है।

विपक्ष ने मोस्तकुर को गवर्नर बनाने पर विरोध जताया : मोस्ताकुर की नियुक्ति के बाद विपक्षी नेता शफीकुर रहमान ने फेसबुक पर लिखा कि बांग्लादेश बैंक में जो हो रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि किसी को भी गवर्नर और उनके सलाहकारों जैसे सम्मानित लोगों को इस तरह अपमानित करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब देश की अर्थव्यवस्था पहले से कई समस्याओं से जूझ रही है, तब बांग्लादेश बैंक जैसी महत्वपूर्ण संस्था में इस तरह की कार्रवाई बची हुई अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद कर देगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और समाज के सभी वर्गों से विरोध करने की अपील की और कहा कि अगर सरकार सच में लोकतांत्रिक और भेदभाव-रहित बांग्लादेश बनाना चाहती है तो ऐसी गतिविधियां तुरंत बंद होनी चाहिए। जरूरी पदों पर नियुक्तियां योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, न कि राजनीतिक निष्ठा के आधार पर।

अहसान हबीब को गवर्नर पद से हटाने का विरोध : विवाद की दूसरी बड़ी वजह उनकी नियुक्ति की परिस्थितियां हैं। अहसान हबीब मंसूर 2024 में चार साल के लिए गवर्नर बनाया गया था और उनका कार्यकाल अगस्त 2028 तक था, लेकिन 18 महीने से भी कम समय में ही उनका कार्यकाल खत्म कर दिया गया। मंसूर को हटाए जाने से पहले कुछ अधिकारियों ने उनके खिलाफ तानाशाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया था। हालांकि, मंसूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन आरोपों को साजिश बताया था।

अहसान हबीब मंसूर की बर्खास्तगी से देश में कई लोग हैरान हैं। उन्हें 27 साल का अनुभव है। वे आईएमएफ जैसी संस्थाओं में काम कर चुके हैं। 2024 में शेख हसीना और उनकी अवामी लीग सरकार के हटने के बाद जब देश में आर्थिक अस्थिरता थी, तब उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। जब उन्होंने पद संभाला था तब फॉरेन करेंसी रिजर्व 26 अरब डॉलर था। उनके पद छोड़ने तक यह बढ़कर 35 अरब डॉलर हो गया। उन्होंने टका को 122.20 प्रति डॉलर पर स्थिर किया और महंगाई दर को 2024 के 10.49% से घटाकर जनवरी 2026 में 8.58% तक लाने के लिए पॉलिसी अपनाई।

जिनेवा में यूएस-ईरान परमाणु वार्ता हुई पूरी, पश्चिम एशिया में सैन्य जमावड़े से युद्ध की आशंका

जिनेवा, एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर अप्रत्यक्ष वार्ता हुई। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हो रही इस बातचीत पर पूरी दुनिया की नजर टिकी थी, क्योंकि इसी के साथ पश्चिम एशिया में सैन्य हलचल भी तेज हो गई है। वार्ता का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करना और संभावित युद्ध को टालना बताया गया है, जबकि अमेरिका पश्चिम एशिया में अपने विमान और युद्धपोतों का बड़ा बेड़ा तैनात कर रहा है।

युद्ध टालने की कोशिश, लेकिन खतरा बरकरार : ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने जिनेवा रवाना होने से पहले चेतावनी दी कि अगर अमेरिका हमला करता है तो क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने निशाने पर होंगे। उन्होंने कहा यह किसी के लिए जीत की स्थिति नहीं होगी। पूरा क्षेत्र एक विनाशकारी युद्ध की चपेट में आ सकता है। ईरान पहले ही संकेत दे चुका है कि वह इस्राइल को भी निशाना बना सकता है, जिससे पूरे मध्य पूर्व में बड़े संघर्ष की आशंका बढ़ गई है।

पिछले साल युद्ध से टूटी थी बातचीत : पिछले वर्ष कई दौर की वार्ता उस समय पटरी से उतर गई थी जब इस्राइल ने ईरान पर 12 दिन तक हमले किए और अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर भारी बमबारी की। हालांकि नुकसान की पूरी तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि ईरान फिलहाल यूरेनियम संवर्धन नहीं कर रहा, लेकिन वह उस स्तर तक पहुंचने की कोशिश में है जहां से परमाणु हथियार बनाना संभव हो सके।

खाड़ी क्षेत्र में बढ़ी सैन्य हलचल : उधर, अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े के जहाजों की गतिविधियों में भी बदलाव देखा गया है। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिला है कि बहरीन स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे से कई पोत समुद्र में तैनात किए गए हैं। तेल बाजार भी इस तनाव से प्रभावित है। ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 70 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। पिछली वार्ता के दौरान ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में आवाजाही अस्थायी रूप से रोकने का संकेत दिया था, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर पड़ा था।

किम जोंग-उन की साउथ कोरिया को चेतावनी, बोले- खतरा हुआ तो 'पूरी तरह तबाह' कर देंगे

प्योंगयांग, एजेंसी। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग-उन ने साउथ कोरिया को कड़ी चेतावनी दी है। किम ने कहा है कि उनके देश की सुरक्षा को खतरा हुआ तो वे साउथ कोरिया को 'पूरी तरह नष्ट' कर सकते हैं। प्योंगयांग में सात दिन चली वर्कर्स पार्टी कांग्रेस के समापन पर किम ने अगले पांच वर्षों के लिए परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को तेज करने का खाका पेश किया। उन्होंने पानी के भीतर से दागे जा सकने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सामरिक परमाणु हथियारों के विस्तार, परमाणु-संचालित पनडुब्बी, एआई-युक्त ड्रोन और उन्नत उपग्रह विकसित करने की बात कही। किम ने साउथ कोरिया को 'स्थायी दुश्मन' बताते हुए कहा कि उससे बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं, उन्होंने कहा कि अमेरिका यदि प्रतिबंध और दबाव की नीति छोड़े तो संवाद संभव है। कांग्रेस के बाद राजधानी में भव्य सैन्य परेड आयोजित की गई, जिसमें किम अपनी बेटी के साथ नजर आए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि किम एक ओर अपने परमाणु कार्यक्रम को मजबूती दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिका के साथ भविष्य की संभावित बातचीत के लिए विकल्प भी खुले रख रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र की जांचकर्ता पर अमेरिकी प्रतिबंध : वाशिंगटन, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार जांचकर्ता फ्रांसेस्का अल्बानीज के परिवार ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। उनका कहना है कि इस्राइल की आलोचना करने पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंध अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन हैं। अल्बानीज ने गाजा में इजराइली कार्रवाई को 'जनसंहार' बताया था, जिसे अमेरिका और इस्राइल ने खारिज किया। परिवार का कहना है कि प्रतिबंधों से उनका निजी और पेशेवर जीवन प्रभावित हुआ है।

'जो होना है, वह हमने बता दिया', यूरेनियम संवर्धन पर ईरानी विदेश मंत्री अराघची की अमेरिका को दो टूक

जिनेवा, एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के दौरान जिनेवा में दोनों देशों ने वार्ता की। कई घंटों की बैठक के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि यह गहरी चिंता भरी लंबी बातचीतों में से एक है। जिनेवा में अब तक हुई इन चर्चाओं के बाद कोई समझौता नहीं हो सका, जिससे पश्चिम एशिया में फिर से युद्ध की आशंका बनी हुई है। अब्बास अराघची ने गुरुवार को ईरानी सरकारी टीवी से बातचीत में कहा कि जो कुछ होना है, वह हमारी ओर से साफ कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने बातचीत के विवरण साझा नहीं किए। अमेरिकी पक्ष की ओर से भी तत्काल कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई और व्हाइट हाउस ने भी प्रतिक्रिया नहीं दी।

अगले हफ्ते फिर होगी अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत जिनेवा में हुई कई घंटों की अप्रत्यक्ष वार्ता के बावजूद दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका। वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल-बुसैदी ने कहा कि बातचीत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हालांकि, उन्होंने भी विस्तार से जानकारी नहीं दी। आगे की वार्ता का दौर अगले सप्ताह वियना में होगा, जहां अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है। वार्ता समाप्त होने से ठीक पहले ईरानी सरकारी टीवी ने बताया कि तेहरान यूरेनियम संवर्धन जारी रखने के अपने अधिकार पर अडिग है और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहा है। यह रुख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मांगों से अलग माना जा रहा है। ट्रंप की मांग है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन, लंबी दूरी की मिसाइल कार्यक्रम पूरी तरह रोके। इसके साथ ही हमास और हिजबुल्लाह जैसे समूहों को समर्थन देना बंद करे। वहीं, ईरान का कहना है कि वह केवल परमाणु मुद्दे पर बात करेगा। अराघची ने फिर दी चेतावनी अराघची ने एक साक्षात्कार में फिर से चेतावनी दी कि अगर अमेरिका हमला करता है तो क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने वैध लक्ष्य माने जाएंगे और इससे व्यापक क्षेत्रीय युद्ध छिड़ सकता है। उन्होंने इसे बहुत डरावना बताते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में किसी की जीत नहीं होगी।

'अमेरिका के लिए बड़ी जीत', व्हाइट हाउस बॉलरूम प्रोजेक्ट पर कोर्ट की हरी झंडी के बाद गदगद ट्रंप

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक संघीय जज के फैसले का स्वागत किया है। जज ने व्हाइट हाउस में बन रहे नए बॉलरूम (विशाल हॉल) के निर्माण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद ट्रंप ने इसे 'अमेरिका के लिए शानदार खबर' बताया।

संरक्षण समूहों की मांग जज ने की खारिज : यह मामला तब शुरू हुआ जब कुछ संरक्षण समूहों ने अदालत में याचिका दायर की। उनका कहना था कि व्हाइट हाउस में इतना बड़ा निर्माण करने से पहले कांग्रेस की मंजूरी, स्वतंत्र समीक्षा और आम जनता से राय लेने जैसी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी नहीं की गईं। उन्होंने अदालत से निर्माण

कार्य रोकने की मांग की थी। लेकिन जज ने उनकी मांग खारिज कर दी।

जज के फैसले के बाद गदगद दिखे ट्रंप : फैसले के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट लिखकर कहा कि यह दुनिया का सबसे सुंदर बॉलरूम होगा। उन्होंने साफ कहा कि इस प्रोजेक्ट में एक भी डॉलर टैक्सपेयर्स का पैसा नहीं लग रहा है। उनके मुताबिक पूरा खर्च 'देशभक्त दानदाताओं' और निजी योगदान से उठाया जा रहा है।

क्या है व्हाइट हाउस का बॉलरूम प्रोजेक्ट : यह बॉलरूम करीब 90,000 वर्ग फुट का होगा। इसका उपयोग भविष्य में शपथ ग्रहण समारोह, बड़े स्टेट विजिट, राजकीय भोज और बड़े कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार यह प्रोजेक्ट 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है।

निजी दान से आ रहा पूरा पैसा- ट्रंप प्रशासन : इस निर्माण के लिए पहले अनुमानित लागत 200 मिलियन डॉलर (1,820 करोड़ रुपए) बताई गई थी, लेकिन अब यह बढ़कर लगभग 300 मिलियन डॉलर (2,730 करोड़ रुपए) हो गई है। प्रशासन का कहना है कि पूरा पैसा निजी दान से आ रहा है, जबकि आलोचकों का कहना है कि इतनी बड़ी संरचना व्हाइट हाउस की ऐतिहासिक पहचान को बदल देगी। अगर यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, तो यह ट्रंप के कार्यकाल में व्हाइट हाउस में किया गया सबसे बड़ा भौतिक बदलाव माना जाएगा।

अफगानिस्तान के नये कानून पर यूएन ने जताई गंभीर चिंता

एथेंस, एजेंसी। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने नया दंड संहिता लागू किया है। इस कानून पर जनवरी में वहां के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने हस्ताक्षर किए थे। इस नए कानून में कुल 119 धाराएं हैं और इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं, जिन पर संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है।

पत्नी को पीटने पर सिर्फ 15 दिन की सजा : सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून में पत्नी को पीटने पर सजा सिर्फ 15 दिन की जेल रखी गई है, वह भी तब जब पत्नी अदालत में साबित कर दे कि उसे चोट लगी है और शरीर पर कट, घाव या नीला निशान दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर, अगर कोई महिला अपने पति की अनुमति के बिना अपने मायके चली जाती है और वहां रुकती है, तो उसे तीन महीने की जेल हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर उसके मायके वाले उसे वापस पति के पास नहीं भेजते, तो उन्हें भी सजा दी जा सकती है।

यह कानून अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ- तुर्क : संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने कहा है कि यह कानून अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है और महिलाओं के साथ भेदभाव को कानूनी रूप देता है। यूएन वुमेन की प्रतिनिधि सुसान फर्ग्यूसन ने भी कहा कि इस कानून से पुरुषों को महिलाओं पर अधिकार की स्थिति में रखा गया है और महिलाओं के लिए न्याय पाना और मुश्किल हो जाएगा। इस कानून में एक और चौंकाने वाली बात यह है कि जानवरों को लड़ाने पर पांच महीने तक की जेल हो सकती है। अफगानिस्तान में मुर्गों और तीतरों की लड़ाई एक आम परंपरा रही है, लेकिन तालिबान ने 2021 में सत्ता में आने के बाद इस पर रोक लगा दी थी। अब नए कानून में जानवरों की लड़ाई की सजा पत्नी को गंभीर रूप से पीटने की सजा से कहीं ज्यादा है।

एक ही अपराध के लिए अलग सजा : सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक ही अपराध के लिए अलग-अलग सामाजिक वर्गों के लोगों को अलग सजा दी जाएगी। धार्मिक विद्वानों और बड़े लोगों को सिर्फ चेतावनी दी जा सकती है, जबकि आम लोगों को जेल और निचले वर्ग के लोगों को शारीरिक सजा दी जा सकती है। हालांकि हत्या के मामलों में यह फर्क नहीं होगा और दोषी पाए जाने पर मौत की सजा दी जा सकती है। पैगंबर मोहम्मद का अपमान भी मौत की सजा वाला अपराध है, हालांकि पश्चाताप करने पर इसे छह साल की जेल में बदला जा सकता है।

पाकिस्तान की सेना हमलावरों को नेस्तनाबूत करने में सक्षमः शहबाज शरीफ

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध जैसा माहौल बन गया है। पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक का बदल लेने के लिए अफगानिस्तान ने डूरंड लाइन के इलाके में हमला किया तो पाकिस्तान ने सीधा राजधानी काबुल को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने काबुल की 12 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। वहीं अफगानिस्तान ने इसे आतंकी हमला बताया है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना हमलावरों को नेस्तनाबूत करने में सक्षम है।

उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, हमारी सेनाओं के पास हमलावरों को कुचलने की ताकत है। इस स्थिति में पूरा देश सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वहीं अफगानिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान ने शुक्रवार तड़के काबुल और दो अन्य प्रांतों में हवाई हले किए हैं। ऐसे में अब कतर की मध्यस्थता में कराया गया युद्धविराम कमजोर हो गया है।

काबुल में तीन विस्फोट : काबुल में कम से कम तीन विस्फोटों की आवाज सुनी गई, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि राजधानी में हमले कहां हुए और इनमें किसी के हताहत होने की जानकारी भी तुरंत नहीं मिल सकी। सरकारी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि पाकिस्तान ने दक्षिण में कंधार और दक्षिण-पूर्वी प्रांत पकतिया में भी हवाई हमले किए।

पाक ने अफगानिस्तान पर लगाए बिना उकसावे के हमले के आरोप : मुजाहिद ने बृहस्पतिवार रात 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''पाकिस्तानी सेना के बार-बार विद्रोह और हमलों के जवाब में डूरंड रेखा के पास स्थित पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों और प्रतिष्ठानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए।'' अफगान रक्षा मंत्रालय ने

कहा कि जवाबी हमले सीमा से लगे छह प्रांतों में किए गए। दोनों देशों के बीच 2,611 किलोमीटर लंबी सीमा को डूरंड रेखा कहा जाता है, जिसे अफगानिस्तान औपचारिक रूप से मान्यता नहीं देता।

यूएन ने भी संघर्ष पर जताई चिंता : इस बीच, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने सीमा पार झड़पों की खबरों पर चिंता जताई। उनके प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि महासचिव ने दोनों पक्षों से मतभेदों को कूटनीति के जरिए सुलझाने की अपील की है। दोनों देशों ने हताहतों के अलग-अलग आंकड़े दिए। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जिनमें से कुछ के शव अफगानिस्तान ले जाए गए, जबकि ''कई सैनिकों को जिंदा पकड़ लिया गया।'' मंत्रालय के अनुसार, अफगानिस्तान के आठ सैनिक मारे गए और 11 घायल हुए।

दूसरी ओर पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने कहा कि पाकिस्तान के दो सैनिक मारे गए और तीन घायल हुए हैं, जबकि 36 अफगान लड़ाके मारे गए। पिछले कई महीनों से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। अक्टूबर में सीमा पर हुई झड़पों में सैनिकों, नागरिकों और संदिग्ध आतंकियों की मौत हुई थी। हालांकि, कतर की मध्यस्थता से हुआ युद्धविराम काफी हद तक लागू रहा लेकिन सीमा पर बीच-बीच में गोलीबारी होती रही है। नवंबर में हुई कई दौर की शांति वार्ताएं भी किसी औपचारिक समझौते पर नहीं पहुंच सकीं।

आईआरएस द्वारा गोपनीय जानकारी साझा करने पर अदालत की टिप्पणी : वाशिंगटन, एजेंसी। एक अमेरिकी जज ने कहा है कि टैक्स विभाग आईआरएस ने लगभग 42,695 बार गोपनीय करदाता जानकारी इमिग्रेशन एजेंसी आईसीई के साथ साझा कर कानून तोड़ा। अदालत के अनुसार, बिना उचित कानूनी आधार के पतों की जानकारी दी गई। सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील कर रही है, लेकिन फिलहाल अदालत ने इसे गोपनीयता कानून का उल्लंघन माना है।

स्विस बैंक पर अमेरिकी कार्रवाई : वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका ने एक छोटे स्विस बैंक पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। आरोप है कि बैंक ने ईरान और रूस से जुड़े लोगों के 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा धन को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली के जरिए स्थानांतरित किया। ट्रेजरी विभाग का कहना है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।

संक्षिप्त समाचार

धारदार हथियार से हमला, छह आरोपियों पर प्राथमिकी

वाराणसी, एजेंसी। मिर्जामुराद के खोचवां भेड़हा गांव में 23 फरवरी को धारदार हथियार से हमले के मामले में पलिस ने पांच दिन बाद आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सबाना बेगम ने पुलिस को तहरीर में आरोप लगाया है कि 23 फरवरी को विपक्षी इरसाद शेख, समसुन निशा, मो. सैफ अली, मो. कैफ अली निवासी भेड़हा और जावेद अली निवासी रहीमपुर (लोहता) ने मारपीट की। बीचबचाव करने पहुंचे समसुद्दीन व उनकी पत्नी नूरजहां बेगम पर भी धारदार हथियार से हमला किया। प्रभारी प्रमोद कुमार पांडेय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

बोर्ड परीक्षा के बाद मारपीट, ईंट मारकर छात्र की हत्या

गोरखपुर, एजेंसी। कोतवाली इलाके के बेनीगंज स्थित डीबी इंटर कॉलेज में बुधवार शाम यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद मामूली बात पर हुई मारपीट में छात्र अंकुर सिंह (18) की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी छात्र सत्यम गौड़ को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, कुशीनगर जिले के अहिरौली इलाके के सोमली पेमली गांव निवासी जनार्दन सिंह का बेटा अंकुर पादरी बाजार स्थित ईस्टर्नपुर में सेंट मेरी इंटर कॉलेज में इंटर का छात्र था। उसका सेंटर डीबी इंटर कॉलेज में गया था। बुधवार को दूसरी पाली में वह फिजिक्स की परीक्षा देने गया था। आरोप है कि परीक्षा खत्म होने के बाद स्टैंड में बाइक खड़ी करने की बात पर एम्स इलाके के छात्र सत्यम कुमार गौड़ से उसकी बहस हो गई। इसी दौरान आरोपी सत्यम ने ईंट से अंकुर पर हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से अंकुर वहीं अचेत हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस परिजनों को सूचना देने के साथ छात्र को जिला अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख लखनऊ रेफर कर दिया। परिजन रात एक बजे के करीब लखनऊ लेकर पहुंचे जहां इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव बृहस्पतिवार की देर शाम घर लाया गया।अंकुर के बड़े भाई अमन सिंह ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी छात्र के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने घटना वाले दिन ही हत्या की कोशिश में प्राथमिकी दर्ज की थी। अंकुर की मौत के बाद मामले में हत्या की धारा बढ़ा दी गई।

मेरठ बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी ने ली शपथ

मेरठ, एजेंसी। मेरठ कचहरी स्थित पंडित नानकचंद सभागार में बृहस्पतिवार को मेरठ बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित प्रबंध समिति का शपथ ग्रहण समारोह अत्यंत हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि जिला जज मेरठ अनुपम कुमार की उपस्थिति में नई टीम ने अधिवक्ता हितों की रक्षा का संकल्प लिया। मंच पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनुज कुमार शर्मा और महामंत्री परवेज आलम मौजूद रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में पूर्व समिति के महामंत्री राजेन्द्र सिंह राणा ने अपने कार्यकाल का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। इसके पश्चात अतिथियों, चुनाव अधिकारियों और पूर्व प्रबंध समिति के पदाधिकारियों को प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया गया। चुनाव अधिकारी रउफउल हसन अंसारी, जगदीश गिरी, नेपाल सिंह सोम, अशोक पंडित, विरेन्द्र सिंह सिरोही, मनोज गुप्ता, सतेन्द्र सिंह, मनुज बुटार और सहदेव सिंह सोम ने विजेताओं के नामों की आधिकारिक घोषणा की और सभी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद महामंत्री परवेज आलम ने कहा, अधिवक्ताओं ने जो विश्वास हम पर जताया है, हम उस पर पूरी तरह खरे उतरेंगे और उनके हितों के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। समारोह में कई न्यायिक अधिकारियों सहित वरिष्ठ अधिवक्ता एमपी शर्मा, डी.डी. शर्मा, अनिल कुमार बक्शी, डॉ. ओपी शर्मा, अब्दुल जब्बार खान, कुंवर पाल शर्मा, अमित दीक्षित, वीके शर्मा, मिसबाहुद्दीन सिद्दिकी, नरेश दत्त शर्मा, प्रबोध शर्मा, आनंद कश्यप, राजकुमार गुर्जर, संदीप कुमार बंसल और सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।

डॉक्टर और हिस्ट्रीशीटर की कॉल डिटेल से खुली बिहार के माफिया से सांठगांठ

गोरखपुर, एजेंसी। कैंट थाना क्षेत्र में डॉक्टर से कथित रंगदारी मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने जब कॉल डिटेल खंगाली तो हिस्ट्रीशीटर से लगातार संपर्क सामने आया। इसमें कई राज भी खुले हैं। जांच में बिहार के मरीज माफिया से सांठगांठ की बात भी सामने आई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, बिहार के साथ-साथ आसपास के जिलों से भी मरीजों को सुनियोजित तरीके से लाया जाता था। मरीज लाने के नाम पर एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा था, जिसमें कमीशनखोरी और दबाव की रणनीति अपनाई जाती थी। डॉक्टर के बयान के बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अब फोकस मरीज माफिया के नेटवर्क की पहचान, आर्थिक लेनदेन और आपसी संपर्कों की पड़ताल पर है।अब तक की जांच में पता चला कि डॉ. पंकज पहले अपने अस्पताल में बिहार से मरीज लाने के लिए बिट्टू खान की एंबुलेंस सर्विस का उपयोग करते थे। इसके बदले कमीशन का भुगतान करते थे। मगर हाल के दिनों में बिट्टू ने मरीजों को मानसी अस्पताल के बजाय सान्वी अस्पताल में भेजना शुरू कर दिया।सूत्रों ने बताया कि मरीजों और उनके परिजनों को मानसिक दबाव में रखा जाता है। उन्हें विश्वास दिलाया जाता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका मरीज सुरक्षित रहेगा। वहां बेहतर इलाज मिलेगा। एजेंट और एंबुलेंस चालकों के लिए अस्पताल के बिल का 30 प्रतिशत हिस्सा कटता है। जिन डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन होते हैं, उन्हें इस नेटवर्क में शामिल होने के बदले लाखों रुपये मिलते हैं।दरअसल, मानसी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर पंकज दीक्षित ने 16 फरवरी को दर्ज मामले में बताया था कि उनसे 15 लाख की रंगदारी मांगी गई है। इसके 24 घंटे बाद ही एक ऑडियो सामने आया जिसमें दो तरह की हेराफेरी सामने आई थी। पहला मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कराना और दूसरा बिहार बॉर्डर के मरीजों को गोरखपुर के हॉस्पिटल तक लाने के बदले कमीशन देने का। इसकी डील भी लाखों में होती है। ऑडियो में डॉक्टर और बिहार के मरीज माफिया बातचीत कर रहे हैं।इसमें कमीशन के बदले मरीजों को लेकर आने वाली एंबुलेंस के मालिक को भला-बुरा कहा जा रहा है। पुलिस अब बिहार के मरीज माफिया की तलाश में जुटी है।इस संबंध में एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। डॉक्टर का बयान दर्ज कर लिया गया है।

सीएम योगी बोले- न बने और न बिके अवैध शराब

लखनऊ, एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व समीक्षा बैठक में अवैध व जहरीली शराब पर सख्ती के निर्देश दिए। वित्तीय वर्ष 2025-26 में फरवरी तक 1.96 लाख करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुआ है। जीएसटी-वेट से एक लाख करोड़ से अधिक संग्रह हुआ। सभी विभागों को लक्ष्य समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिए कि आबकारी विभाग होली के दौरान विशेष सतर्कता बरते और अवैध व जहरीली शराब के किसी भी प्रकार के उत्पादन और बिक्री पर पूरी तरह अंकुश लगाए।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के फरवरी माह के अंत तक जीएसटी, वैट, आबकारी, स्टाम्प एवं पंजीकरण, परिवहन, ऊर्जा, भू-राजस्व और खनन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व वृद्धि प्रदेश में विकास कार्यों की गति तय करता है।

इस पर उन्हें बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कर-राजस्व का वार्षिक लक्ष्य 2,95,000 करोड़ निर्धारित है, जिसके सापेक्ष फरवरी 2026 तक 1,96,177 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को टीम भावना, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग से लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन के लिए रजिस्ट्री कार्यालयों के आधुनिकीकरण की गति बढ़ाने को कहा। परिवहन विभाग को बसों की फिटनेस, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ठोस कार्ययोजना और नए रूट चिन्हित कर निजी बस संचालकों के सहयोग से बेहतर परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

जीएसटी व वैट से राजस्व एक लाख करोड़ पार : राज्य कर (जीएसटी + वैट) का लक्ष्य 1,75,725 करोड़ है, जिसके मुकाबले अभी तक 1,03,770 करोड़ का संग्रह प्राप्त हुआ है। इसमें जीएसटी के तहत 75,195 करोड़ और वैट से 28,575 करोड़ शामिल हैं। राज्य कर विभाग ने बताया कि जीएसटी 2.0 में

एआई आधारित जोखिम विश्लेषण, बड़े पैमाने पर स्क्रूटनी, ई-इनवॉइसिंग और ई-वे बिल की प्रभावी निगरानी जैसे प्रयासों से सुधार हुआ है। एआई आधारित 1.59 लाख करदाताओं की जांच, 75 जिलों में संवाद कार्यक्रम, फर्जी आईटीसी पर नियंत्रण और 3,117 करोड़ की वसूली विभाग के प्रमुख परिणाम रहे।

आबकारी में जबर्दस्त तेजी, अबतक मिले 48000 करोड़ : आबकारी विभाग ने बताया कि वार्षिक लक्ष्य 63,000 करोड़ है, जिसके सापेक्ष फरवरी तक 48,501 करोड़ का राजस्व मिला है। जो पिछले वर्ष के मुकाबले 13.2 प्रतिशत अधिक है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दुकानों के नवीनीकरण की दर 93.75 प्रतिशत दर्ज की गई है। विभाग ने उपभोग आधारित रणनीति, दुकानों के नवीनीकरण, लाइसेंस शुल्क, मांग पत्र और थोक एवं ब्रांड नवीनीकरण से मार्च में लगभग 9,050 करोड़ राजस्व प्राप्त किया। 31 मार्च तक राजस्व लगभग 57,550 करोड़ पहुंचने का अनुमान है।

स्टांप ने अभी तक दिए 29 हजार करोड़ : स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग ने लक्ष्य 38,150 करोड़ के सापेक्ष फरवरी तक 29,487 करोड़ प्राप्त किए। विभाग ने यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी सहित विभिन्न विकास प्राधिकरणों की आवासीय एवं वाणिज्यिक परियोजनाओं से संभावित राजस्व का भी ब्योरा दिया। खनन पट्टों के नवीनीकरण, अवशेष संपत्तियों के पंजीकरण अभियान, टोल प्लाजा मामलों के निस्तारण और सर्किल दरों के वैज्ञानिक पुनरीक्षण की जानकारी दी।

डिजिटल मानीटरिंग करेगा परिवहन विभाग : परिवहन विभाग का वार्षिक लक्ष्य 14,000 करोड़ है, जिसके मुकाबले फरवरी तक 11,005 करोड़ का राजस्व मिला है। वाहन पंजीकरण में सुधार, कर अदायगी की बेहतर व्यवस्था, तकनीक आधारित निगरानी और प्रवर्तन से राजस्व बढ़ा है।कर वसूली शिविर, निगरानी अभियान और डिजिटल मॉनिटरिंग की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई। भू-राजस्व एवं ऊर्जा विभाग ने संयुक्त रूप से फरवरी तक 3,414 करोड़ का राजस्व संग्रह किया जो पिछले वर्ष से 12.6 प्रतिशत ज्यादा है।

खनन एवं भू-तत्व विभाग ने 6,000 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष फरवरी तक 3597 करोड़ कर चुका है। विभाग ने बताया कि खनन क्षेत्रों की डिजिटल मैपिंग, ओवरलोडिंग की जीरो पॉइंट रोकथाम, जीपीएस आधारित ट्रैकिंग, विभिन्न राज्यों के पोर्टलों से इंटीग्रेशन आदि से राजस्व संग्रह बढ़ा है।

एमईएस कॉलोनी स्टेशन पर फिलहाल नहीं रुकेगी मेरठ साउथ से मोदीपुरम जाने वाली मेट्रो

मेरठ, एजेंसी। मेट्रो मेट्रो शुरू हुई नहीं कि तकनीकी खराबी आ गई है। मोदीपुरम से मेरठ साउथ जाने वालीं मेट्रो एमईएस कॉलोनी स्टेशन पर रुकेगी। वहीं यात्रियों के साथ कर्मचारियों ने अभद्रता की, जिससे उनके प्रशिक्षण की कमी साफ नजर आई।

दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस (नमो भारत) कॉरिडोर के एमईएस कॉलोनी स्टेशन का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। तकनीकी खराबी के कारण इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर फिलहाल ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया है। एनसीआरटीसी का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा और परिचालन संबंधी कारणों से यह निर्णय लिया है।

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि कुछ तकनीकी समस्या के कारण मेरठ साउथ से मोदीपुरम जाने वाली मेट्रो फिलहाल एमईएस कॉलोनी स्टेशन पर नहीं रुकेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर लगातार घोषणाएं की जा रही हैं और नोटिस भी लगाए गए हैं। प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि व्यवस्था सामान्य होने तक वे एमईएस स्टेशन के बजाय उससे पहले या अगले स्टेशन का उपयोग करें। अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि इस बदलाव के कारण यात्रियों को किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी। साथ ही बताया कि मोदीपुरम से मेरठ साउथ जाने वालीं मेट्रो इस स्टेशन पर रुकेंगी।

व्यवस्था की कमी से यात्री परेशान, एक घंटे तक नहीं दिया बाहर जाने : एमईएस स्टेशन पर मेट्रो को न रोके जाने के निर्णय की जानकारी एनसीआरटीसी ने पहले यात्रियों को नहीं दी थी। इस लापरवाही का खमियाजा आम यात्रियों को भुगतना पड़ा। शुक्रवार को शताब्दीनगर से एमईएस स्टेशन के लिए यात्रा कर रहे अजय कुमार भी इस लापरवाही का शिकार हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले तो उन्हें मेट्रो के एमईएस स्टेशन पर नहीं रुकने की जानकारी नहीं दी गई और जब उन्होंने स्टेशन स्टाफ से बात की तो उन्होंने अभद्र व्यवहार किया। करीब एक घंटे तक उन्हें स्टेशन से नहीं जाने दिया। स्टाफ उनसे 210 रुपये जुर्माना मांग रहा था, हालांकि बाद में उच्चाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद यात्री को जाने दिया गया।

अजय कुमार ने बताया कि उन्होंने 30 रुपये का ऑनलाइन टिकट लेकर शाम 4:50 बजे शताब्दी नगर से अपनी यात्रा शुरू की। आरोप है कि जब वह एमईएस स्टेशन पहुंचे तो मेट्रो नहीं रुकी। इस पर उन्होंने आपातकालीन बटन के जरिए महिला चालक से संपर्क किया। चालक ने तकनीकी खराबी का हवाला देते हुए उन्हें अगले स्टेशन डोरली पर उतरने को कहा। अजय ने बताया कि जब वह डोरली स्टेशन पर उतरे तो वहां तैनात कर्मचारी ने उनकी बात सुनने के बजाय उन पर गलत स्टेशन पर आने का आरोप लगाया और वापस एमईएस जाकर ही बाहर निकलने की बात कही। अजय ने बताया कि जब दूसरी मेट्रो से वापस एमईएस स्टेशन पहुंचे तो वहां के एएफसी गेट पर भी उनका टिकट स्कैन नहीं हुआ। आरोप है कि एमईएस स्टेशन पर तैनात कर्मचारी ने अपनी गलती मानने के बजाय उन पर 210 रुपये का जुर्माना ठोक दिया।

रायबरेली में खस्ताहाल सड़क के विरोध में उतरे ग्रामीण, सड़क नहीं तो वोट नहीं का किया एलान

रायबरेली, एजेंसी। खराब सड़क को लेकर ग्रामीणों ने गांव में जगह-जगह रोड नहीं तो वोट नहीं लिखी होर्डिंग और बैनर टांग दिए और प्रशासन से सड़क बनवाने की मांग की। डलमऊ तहसील तहसील क्षेत्र में उसे समय चर्चा का विषय बन गया जब गांव के लोग रोड नहीं तो वोट नहीं लिखे बैनर टांग दिए। और ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। मामला डलमऊ तहसील क्षेत्र के चक मलिक भीटी का है जहां पर भीटी कनहा मार्ग से पूरे डगरी तक करीब 500 मीटर सड़क 25 वर्षों से अधूरी पड़ी हुई है आज तक ना तो किसी नेता व विधायक, ग्राम प्रधान ने इस सड़क की ओर देखना मुनासिब नहीं समझा। गांव के रत्नो देवी,मिल्की,सुनीता,रामावती सहित दर्जनों ग्रामीणों ने बताया है कि 25 वर्षों से यह मार्ग अधूरी पड़ी है। नेता विधायक से कहा गया। लेकिन, कोई नहीं सुनता और देख कर चले जाते है।एंबुलेंस घर तक नहीं पहुंच पाती है, महिलाओं की दिलावरी के लिए काफी समस्या उठानी पड़ती हैं। जर्जर सड़क के कारण आवागमन में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है बरसात में कीचड़ और भराव से हालात बस से बदतर हो जाते हैं। स्कूली बच्चों बुजुर्गों और मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी उठाना पड़ता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि सड़क नहीं बनी तो आगामी चुनाव में मतदान बहिष्कार किया जाएगा।

3.34 करोड़ का बजट हुआ पारित, भेदभाव पर हंगामा

रायबरेली , एजेंसी। राही ब्लॉक सभागार में शुक्रवार को करीब 12 माह बाद क्षेत्र पंचायत की बैठक हुई। इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तीन करोड़ 34 लाख रुपये का बजट पारित किया गया। हालांकि बैठक के दौरान विकास कार्यों में अधिकारियों पर भेदभाव का आरोप लगाकर हंगामा भी किया गया। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह मामला शांत कराया। सदर विधायक अदिति सिंह की अध्यक्षता में बजट प्रस्तुत किया गया। इसके तहत बताया गया कि डेढ़ से दो करोड़ रुपये के टेंडर प्रक्रियाधीन हैं। आगामी वित्त वर्ष 2026-27 का बजट मिलने पर आगे के प्रस्तावों पर विचार करने की बात कही गई।

क्षेत्र पंचायत सदस्य सोनू पासी ने लोधवारी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महाबली वीरा पासी के पार्क के जीर्णोद्धार के प्रस्ताव को अधिकारियों द्वारा रद्द किए जाने का मुद्दा उठाया। आरोप लगाया कि बीडीओ राही कार्यों को कराने में भेदभाव कर रहे हैं। विधायक ने स्पष्ट किया कि यह कार्य क्षेत्र पंचायत निधि से संभव नहीं था। इसे विधायक निधि से कराया जाएगा। राही ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र यादव उर्फ राजू ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में विकास कार्य प्राथमिकता से कराए जा रहे हैं, जबकि अन्य की उपेक्षा की जा रही है। सेमरा प्रधान प्रतिनिधि चंदन सिंह और भखरवारा प्रधान प्रतिनिधि शैलेंद्र प्रताप उर्फ गट्टू सिंह ने भी क्षेत्र पंचायत से कराए गए कार्यों में भेदभाव का आरोप लगाया।

उमाशंकर के करीबियों के ठिकानों पर खनन के बेनामी पट्टों का खुलासा, अवैध खनन में सबसे अधिक कमाई की

लखनऊ, एजेंसी। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह और उनके करीबियों पर आयकर छापों में खनन के बेनामी पट्टों का खुलासा हुआ है। मिर्जापुर और सोनभद्र में अवैध खनन से कमाई के संकेत मिले हैं। 100 से अधिक बैंक खाते चिन्हित कर फ्रीज करने की प्रक्रिया जारी है। टैक्स चोरी का आकलन किया जा रहा है।

बसपा विधायक उमाशंकर सिंह और उनके करीबियों के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापों में बड़ा खुलासा हुआ है। बीते तीन दिन से लखनऊ, मिर्जापुर और सोनभद्र में विधायक के करीबियों के ठिकानों पर छानबीन में खनन के बेनामी पट्टे लेने का पता चला है। खासकर राजधानी के सदर बाजार निवासी इश्तियाक ने सर्वाधिक बेनामी पट्टे लिए थे। उसे पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति का करीबी भी बताया जाता है। अधिकारियों के मुताबिक मिर्जापुर और सोनभद्र में अधिकतर बेनामी पट्टे लिए गए थे। इसके जरिये बड़े पैमाने पर अवैध खनन को भी अंजाम दिया गया। जांच में कई स्थानीय अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है, जो पट्टाधारकों से उगाही कर रहे थे। आयकर विभाग जल्द ही इन अधिकारियों को पूछताछ के लिए नोटिस देकर तलब करेगा। वहीं, दूसरी ओर आयकर विभाग ने विधायक, उनके परिजनों, कंपनियों और करीबियों के 100 से ज्यादा बैंक

खातों और लॉकर्स को चिह्नित किया है, जिन्हें फ्रीज कराने का निर्देश बैंकों को दिया गया है। छापों में यूपी समेत कई राज्यों में बेशकीमती संपत्तियों की खरीद-फरोख्त करने के सुराग भी मिले हैं।

आयकर विभाग विधायक और उनके करीबियों के ठिकानों पर छानबीन में मिले सबूतों के आधार पर टैक्स चोरी का आकलन कर रहा है। हालांकि बड़े पैमाने पर अघोषित लेन-देन के सामने आने की वजह से इसमें देरी हो रही है। सूत्रों की मानें तो विधायक और उनके करीबियों पर टैक्स चोरी का आकलन होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खासकर अवैध खनन की कमाई को निवेश करने के मामले में वह बुरी तरह फंस सकते हैं। इंवेस्टिगेशन विंग द्वारा आगे इस प्रकरण को बेनामी संपत्ति निषेध इकाई को ट्रांसफर करने से उनको पाई-पाई का हिसाब देना पड़ेगा।

होजरी की दुकान में चोरी करती दिखीं तीन महिलाओं की तलाश जारी

वाराणसी, एजेंसी। चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर में एक होजरी की दुकान में दिनदहाड़े हुई चोरी के मामले में दुकान संचालक ने तीन अज्ञात महिलाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फुटेज में दिख रही महिला व्यापार मंडल की कथित पदाधिकारी बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने जांच करने की बात कही। फुटेज में देखा गया कि तीनों महिलाओं ने बातों में उलझाया और झोले में भर लिया।

दुकान संचालक सुदीप सिंह के अनुसार, तीन महिलाएं ग्राहक बनकर दुकान में दाखिल हुईं। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक महिला सेल्स गर्ल को अपनी बातों में उलझाए हुए है, जबकि उसके साथ आई युवती रैक से सामान उठाकर अपने झोले में भर रही है। आरोपियों ने करीब 10 हजार के सामान पर हाथ साफ कर दिया। थाना प्रभारी विजय कुमार शुक्ला ने बताया कि महिलाओं की शिनाख्त कर जल्द ही पूछताछ की जाएगी।

स्वास्थ्य मेले में 578 लोगों ने कराया पंजीकरण

बहराइच , एजेंसी। जरवल विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय तपेसिपाह परिसर में शुक्रवार को आयोजित स्वास्थ्य मेले में स्वास्थ्य सेवाओं और जनजागरूकता का संगम देखने को मिला। मेले का उद्घाटन सीएमओ डॉ. संजय कुमार, एसीएमओ डॉ. संतोष राना व सीएचसी अधीक्षक ने संयुक्त रूप से किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय कुमार ने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है, जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनती है। उन्होंने अभिभावकों से बेटियों की शिक्षा पर जोर देने की अपील की। मेले में कुल 578 लोगों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 447 ने विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। 227 लोगों को निशुल्क दवाएं वितरित की गईं। नेत्र जांच शिविर में 46 लोगों की जांच हुई, जिनमें 30 में मोतियाबिंद के लक्षण मिले और छह ने ऑपरेशन के लिए सहमति दी। परिवार नियोजन पर 74 लोगों को परामर्श दिया गया और 16 ने अस्थायी साधन अपनाए। आयुष्मान भारत योजना के तहत 32 गोल्डन कार्ड बनाए गए। 26 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और 22

लविवि न्यू कैंपस के सभी महिला छात्रावासों की जिम्मेदारों को हटाया, नई टीम तैनात

लखनऊ, एजेंसी। लखनऊ विश्वविद्यालय न्यू कैंपस के गंगा गर्ल्स छात्रावास में खराब भोजन और छात्राओं के विरोध के बाद कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने सभी महिला छात्रावासों की प्रोवोस्ट और सहायक प्रोवोस्ट को हटा दिया। लखनऊ विश्वविद्यालय न्यू कैंपस स्थित गंगा गर्ल्स छात्रावास में मेस के खराब भोजन से छात्राओं की तबीयत बिगड़ने और उसके बाद हुए प्रदर्शन को कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने गंभीरता से लिया है।

उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्राओं को धमकाने पर भी सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को कुलपति ने सख्त रुख अपनाते हुए न्यू कैंपस के सभी महिला छात्रावासों की प्रोवोस्ट, सहायक प्रोवोस्ट और एडिशनल चीफ प्रोवोस्ट को तत्काल प्रभाव से हटा दिया।

बुधवार रात छात्राओं की तबीयत खराब होने और विरोध प्रदर्शन के बाद बृहस्पतिवार को कुलपति गंगा गर्ल्स छात्रावास पहुंचे थे। लगभग तीन घंटे तक उन्होंने छात्राओं की समस्याएं सुनीं। छात्राओं ने एक स्वर में प्रोवोस्ट और असिस्टेंट प्रोवोस्ट की कार्यशैली व उनके व्यवहार पर नाराजगी जताई।

भोजन की गुणवत्ता व व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। शुक्रवार को कुलपति के निर्देश पर कुलसचिव डॉ. भावना मिश्रा ने आदेश जारी कर गंगा छात्रावास और

के प्रमुख पदों की जिम्मेदारी अब विधि संकाय के शिक्षकों को सौंपी गई है।

डॉ. कालिंद्री बनीं एडिशनल चीफ प्रोवोस्ट

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता प्रो. मुकुल श्रीवास्तव ने बताया कि डॉ. कालिंद्री को एडिशनल चीफ प्रोवोस्ट (गर्ल्स) के साथ गंगा गर्ल्स छात्रावास की प्रोवोस्ट तथा डॉ. निहारिका को सहायक प्रोवोस्ट बनाया गया है।

बीआर अंबेडकर छात्रावास के लिए डॉ. ऋचा सक्सेना को प्रोवोस्ट तथा डॉ. श्वेता श्रीवास्तव को डॉ. शशि प्रभा जोशी को सहायक प्रोवोस्ट नियुक्त किया गया है।

खाना सुधरा, छात्राओं ने कहा- थैंक यू वीसी सर

गंगा छात्रावास की छात्राओं ने शुक्रवार को बताया कि कुलपति के दौरे के बाद से भोजन की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। हॉस्टल और मेस में साफ-सफाई की व्यवस्था भी बेहतर हुई है। इसके लिए छात्राओं ने सोशल मीडिया पर थैंक यू वीसी सर का मेसेज पोस्ट कर कुलपति को धन्यवाद ज्ञापित किया।

छात्राओं के आरोपों पर गंभीर हुए कुलपति

छात्राओं के आरोपों को काफी गंभीरता से लिया। अमर उजाला में शुक्रवार को प्रकाशित खबर का भी उन्होंने संज्ञान लिया है जिसमें छात्राओं ने प्रोवोस्ट डॉ. नीतम सिंह पर 'दूसरे तरीके' से देख लेने की धमकी देने के साथ चारित्रिक लांछन लगाने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। कुलपति ने बृहस्पतिवार को छात्रावास पहुंचकर खुद भी देखा था कि वहां क्या स्थिति है। इसके बाद ही कुलपति ने बड़े बदलाव का निर्णय लिया।

इन्हें पद से हटाया गया

न्यू कैंपस के महिला छात्रावासों की जिन प्रोवोस्ट व असिस्टेंट प्रोवोस्ट को पद से हटाया गया है उनमें लावण्या छात्रावास की डॉ. अनुपमा श्रीवास्तव व डॉ. रितु सिंह, गंगा गर्ल्स छात्रावास की डॉ. नीतम सिंह व डॉ. प्रगति श्रीवास्तव तथा बीआर अंबेडकर छात्रावास की डॉ. अर्चना सिंह और ई. निधि श्रीवास्तव हैं।

बदलाव से बेहतरी की उम्मीद

कुलपति ने तय किया है कि अब सप्ताह में एक दिन वह न्यू कैंपस में बैठेंगे। बृहस्पतिवार को हॉस्टल से लौटते ही उन्होंने पांच सदस्यों की टीम बनाई जिसने शाम तक

इस वीकएंड मिलेगा मनोरंजन का तगड़ा डोज, रिलीज होंगी सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर फिल्में-सीरीज

फरवरी का महीना खत्म होने वाला है। इसी के साथ यह वीक भी विदा ले रहा है, मगर मनोरंजन के लिहाज से यह वीकएंड काफी शानदार होने वाला है। होली से पहले मस्ती का भरपूर माहौल है। वहीं, मनोरंजन के लिए ओटीटी पर भी खूब बढ़िया इंतजाम हैं। सस्पेंस से लेकर थ्रिलर और कॉमेडी तक, हर किस्म का ऑप्शन दर्शकों के लिए मौजूद है।

दीपिका पादुकोण नहीं होंगी इंटरनेशनल सीरीज 'द व्हाइट लोटस' का हिस्सा?

दीपिका पादुकोण लंबे वक्त से बड़े पर्दे से दूर हैं। इस बीच पिछले काफी वक्त से दीपिका पादुकोण को लेकर चर्चाएं चल रही थीं कि वो एमी अवॉर्ड विनिंग सीरीज 'द व्हाइट लोटस' के चौथे सीजन में नजर आ सकती हैं, लेकिन अब इन खबरों को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जिससे दीपिका के इस सीरीज का हिस्सा होने न होने के बारे में पता चलता है।

दीपिका नहीं देना चाहती थीं ऑडिशन

जानकारी के अनुसार, दीपिका पादुकोण से इस शो के लिए संपर्क किया गया था और बातचीत भी हुई थी, लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि शो के लिए ऑडिशन देना अनिवार्य था, लेकिन दीपिका ऐसा नहीं करना चाहती थीं, इसलिए वो अब सीरीज का हिस्सा नहीं हैं।

रिपोर्ट में कहा गया कि 'द व्हाइट लोटस' के लिए ऑडिशन कास्टिंग प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। निर्माता कलाकारों को साइन करने से पहले उनका ऑडिशन लेना चाहते थे। दीपिका ऑडिशन देने के लिए इच्छुक नहीं थीं। यही कारण था कि उन्हें 'द व्हाइट लोटस' का मौका छोड़ना पड़ा। यह पहली बार नहीं है, जब शो ने उनसे संपर्क किया है। बताया जा रहा है कि उनसे पहले तीसरे सीजन के लिए भी संपर्क किया गया था, लेकिन तब उन्होंने प्रेग्नेंसी के कारण ऑफर को ठुकरा दिया था।

2017 में दीपिका ने किया हॉलीवुड डेब्यू

हालांकि, अभी तक दीपिका पादुकोण या उनकी टीम की ओर से इन खबरों पर कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है, लेकिन अगर दीपिका इस सीरीज का हिस्सा बनतीं, तो यह उनका दूसरा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होता। दीपिका ने साल 2017 में आई फिल्म जेंडर केज की वापसी से हॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में दीपिका विन डीजल, डोनी येन, क्रिस वू, रूबी रोज, टोनी जा, नीना डोब्रेव और टोनी कोलेट समेत कई जाने-माने कलाकारों के साथ नजर आई थीं।

फ्रांस में हो सकती है चौथे सीजन की शूटिंग

माइक व्हाइट द्वारा निर्मित, लिखित और निर्देशित 'द व्हाइट लोटस' का प्रीमियर 11 जुलाई 2021 को हुआ था। यह ब्लैक कॉमेडी-ड्रामा एंथोलॉजी है, जिसे काफी पसंद किया गया। पहला सीजन हवाई में फिल्माया गया था, इसके बाद दूसरा सीजन सिसिली में और तीसरा सीजन थाईलैंड में फिल्माया गया। अब आगामी चौथे सीजन की शूटिंग फ्रांस में होने की खबर है।

शाहरुख के साथ 'किंग' में नजर आएंगी दीपिका

दीपिका के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो आखिरी बार साल 2024 में आई फिल्म 'सिंघम अगेन' में नजर आई थीं। हालांकि, इस बीच पिछले साल दीपिका अपनी 8 घंटे काम करने की शिफ्ट वाले बयान को लेकर सुर्खियों में रहीं। वहीं उनकी इसी शर्त के चलते उनके 'कल्की 2898 एडी' के सीक्वल और 'स्पिरिट' जैसी फिल्मों से हटने की खबरें भी सुर्खियों में रहीं। अब दीपिका शाहरुख खान के साथ 'किंग' में नजर आएंगी। यह फिल्म इसी साल क्रिसमस पर 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होनी है। इसके अलावा उनकी पाइपलाइन में एटली द्वारा निर्देशित अल्लू अर्जुन की भी एक फिल्म है। काफी बड़े स्तर पर बनने वाली इस फिल्म का टाइटल अभी तक फाइनल नहीं हुआ है।

क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी माध्यम

मराठी फिल्म 'क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी माध्यम' ने सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन किया। अब यह फिल्म ओटीटी पर भी उपलब्ध है। हेमंत धोमे के निर्देशन में बनी इस फिल्म को दर्शक जी5 पर देख सकते हैं। इस फिल्म की कहानी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की वजह से मराठी स्कूलों में घटती बच्चों की संख्या के मुद्दे को दिखाती है।

इसमें दिखाया गया है कि स्कूल के पुराने छात्र और शिक्षक संस्था को बचाने के लिए साथ आते हैं। फिल्म में सचिन खेड़ेकर, अमेय वाघ, सिद्धार्थ चंदेकर, प्राजक्ता कोली, क्षिति जोग, कादंबरी कदम और हरीश दुधाड़े जैसे सितारे अहम रोल में हैं।

द ब्लफ

बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा की हॉलीवुड फिल्म 'द ब्लफ' ओटीटी पर आ चुकी है। इस वीकएंड आप इसे देख सकते हैं। यह फिल्म 25 फरवरी को प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन फ्रैंक ई फ्लॉवर ने किया है। कहानी के केंद्र में एर्सेल 'ब्लडी मैरी' बोडेन (प्रियंका चोपड़ा जोनस) हैं, जो कभी एक खतरनाक समुद्री डाकू रही है।

इक्कीस

दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है। इस फिल्म के जरिए अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने बड़े पर्दे पर डेब्यू किया। श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी फिल्म 'इक्कीस' इस साल पहली जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा फिल्म है, जो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल पर आधारित है। अगस्त्य नंदा ने लीड रोल अदा किया है। यह फिल्म 26 फरवरी को प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई।

'इक कुड़ी'

यह शहनाज गिल अभिनीत फिल्म है। इसमें शहनाज ने दोहरी भूमिका अदा की है। यह फिल्म 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और दर्शकों से इसे अच्छा रेस्पॉन्स मिला था। 26 फरवरी को यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म चौपाल पर रिलीज हो चुकी है। इस वीकएंड इस फिल्म को देख सकते हैं।

अक्यूज्ड

कोंकणा सेन शर्मा और प्रतिभा रांटा अभिनीत फिल्म अक्यूज्ड भी इस वीक की ओटीटी लिस्ट में शामिल है। अनुभूति कश्यप के निर्देशन में बनी यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर 27 फरवरी से स्ट्रीम हो गई है। 'अक्यूज्ड' पोलैंड में सेट सस्पेंस ड्रामा है।

'संगमरमर'

सूरज बड़जात्या के राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी यह सीरीज इस वीक की लिस्ट के लिए शानदार ऑप्शन है। यह कई पीढ़ियों की फैमिली ड्रामा सीरीज है। इसमें अमृता (शीन सविता दास) की कहानी है। उसकी जिंदगी परिवार की जिम्मेदारी और आदित्य (सौरभ राज जैन) के साथ प्यार के बीच एक अहम चुनाव से बदल जाती है। इस सीरीज को परिवार के साथ देखा जा सकता है। 26 फरवरी को यह सीरीज जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई।

'साइको सैयां'

इसके अलावा इस वीकएंड पर रोमांटिक थ्रिलर सीरीज 'साइको सैयां' भी देखी जा सकती है। तेजस्वी प्रकाश, रवि किशन और अनुद सिंह ढाका जैसे सितारों से सजी इस सीरीज ने 24 फरवरी को प्राइम वीडियो पर दस्तक दी।

नेहा कक्कड़

रश्मिका-विजय के बाद अल्लू अर्जुन के भाई अगले महीने करेंगे शादी

अल्लू अर्जुन के घर भी जल्द शादी की शहनाई बजेगी, उनका छोटा भाई अल्लू शिरीष दूल्हा बनेगा। गुरुवार को एक इंस्टाग्राम पोस्ट साझा करते हुए अल्लू शिरीष ने बताया कि वह कब अपनी मंगेतर नयनिका से शादी करने वाले हैं। वह अगले महीने शादी के बंधन में बंधने वाले हैं।

शादी में शामिल होगा सिर्फ परिवार : अल्लू शिरीष ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'नयनिका और मैं, अपने परिवार वालों के बीच शादी करेंगे। हमारी शादी में परिवार के अलावा करीबी दोस्त ही शामिल होंगे। हम 6 मार्च को शादी करने वाले हैं।'

तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लिए चार तीन पहले रखेंगे प्री-वेडिंग रिस्पेशन: अल्लू शिरीष ने आगे अपनी पोस्ट में लिखा, 'हम 2 मार्च को अपना प्री-वेडिंग रिस्पेशन रखेंगे। इसमें तेलुगु इंडस्ट्री के लोग शामिल होंगे। हम इस रिस्पेशन के लिए एक्साइटेड हैं। यह फ़ंक्शन अल्लू स्टूडियो में होगा।' इस तरह अल्लू शिरीष ने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के अपनी शादी में शामिल किया है।

अल्लू शिरीष दो साल से नयनिका को कर रहे थे डेट : अल्लू शिरीष और नयनिका की सगाई पिछले साल 31 अक्टूबर को हुई थी। सगाई से पहले दोनों ने दो साल तक एक-दूसरे को डेट किया था, जिसकी घोषणा उन्होंने सोशल मीडिया पर की थी। इस कपल का रिश्ता तब शुरू हुआ, जब वे अभिनेता नितिन और शालिनी कंदुकुरी द्वारा वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी के लिए आयोजित शादी की पार्टी में मिले थे।

अल्लू शिरीष कॅरियर फ्रंट पर क्या कर रहे हैं? : अल्लू शिरीष को आखिरी बार 2024 में रिलीज हुई एक्शन-कॉमेडी-फैंटेसी फिल्म 'बडी' में देखा गया था। उन्होंने अभी तक किसी आगामी प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं की है, उनका पूरा फोकस अपनी शादी पर है।

होली में रंग जमाने लौटीं नेहा कक्कड़, एक महीने पहले किया था लंबे ब्रेक का ऐलान, यूजर्स ने किया ट्रोल

नेहा कक्कड़ ने जनवरी महीने में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा कर बताया था कि इमोशनल स्ट्रेस, नेगेटिविटी और इंडस्ट्री के दवाब के कारण वह लंबा ब्रेक ले रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया और पैपराजी से दूर रहने की बात की थी, लेकिन होली से पहले ही नेहा कक्कड़ ने अपने एक गाना लॉन्च कर दिया है। इस गाने को लेकर जहां फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया है। ट्रोल्स का कहना है कि ब्रेक का ऐलान करने के बाद वह क्यों लौटीं? साथ ही उनके होली के गाने के बोल भी कुछ यूजर्स को पसंद नहीं आए हैं।

होली के गाने पर ठुमके लगाती दिखीं नेहा: नेहा कक्कड़ ने होली का जो नया गाना गाया है, उसके बोल हैं- 'तेरे साथ में राजा होली खेलूंगीं'। इसमें वह मस्ती भरे अंदाज में होली खेल रही हैं। साथ ही जमकर ठुमके भी लगा रही हैं। इस गाने पर नेहा कक्कड़ का वही अंदाज नजर आ रहा है, जिसके लिए पिछले दिनों वह ट्रोल भी हुईं। इसे गाने में 'सूट टाइट' और 'तेरे लिए करती डाइट' जैसे शब्द भी शामिल हैं।

यूजर्स ने किया खूब ट्रोल: नेहा कक्कड़ का होली सॉन्ग कुछ सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद नहीं आया है। एक यूजर ने लिखा, 'यह हमेशा के लिए रिटायरमेंट क्यों नहीं लेती हैं।' एक अन्य यूजर्स ने लिखा, 'क्या ऊटपटांग गाने बनाती हैं। एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'यह हमेशा के लिए म्यूजिक इंडस्ट्री से ब्रेक क्यों नहीं लेती हैं।' जबकि फैंस नेहा कक्कड़ के सपोर्ट में दिखे, उन्होंने इस होली सॉन्ग को खूब पसंद किया।

पहले भी किया था ब्रेक का ऐलान : नेहा कोई पहली बार ब्रेक पर नहीं गई हैं। वह साल 2020 में भी ब्रेक पर गई थीं। उस वक्त इंडस्ट्री में नेपोटिज्म की बहस चल रही थी। नेहा ने आउटसाइडर होते हुए भी ब्रेक पर जाने की बात कही, लेकिन वह जल्द ही म्यूजिक की दुनिया में लौट आई थीं।

जिसमें मन को खुशी मिले वही काम करें

हर इंसान की पसंद, जरूरतें और प्राथमिकताएं दूसरे से अलग होती हैं। इसलिए दूसरों की बिन मांगी सलाह पर अमल करने के बजाय हमें वही करना चाहिए, जो खुद को सही लगे। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से जूलॉजी में एमएससी किया था। मैं बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छी थी और मुझे टीचिंग का प्रोफेशन बहुत पसंद था। मैं करियर को लेकर ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं हूं और न ही मेरे मन में ज्यादा पैसे कमाने की लालसा है। मेरे पैरेंट्स चाहते थे कि मैं आगे रिसर्च करूं और साइंटिस्ट बनूं। इसलिए उनका मन रखने के लिए मैंने रिसर्च के लिए बीएचयू में अप्लाई कर दिया था और वहां से बुलावा भी आ गया था। इसी बीच बरेली के एक कॉलेज में भी मुझे जॉब मिल गई जिसे छोड़कर मैं बनारस नहीं जाना चाहती थी।

तब परिवार के अलावा दोस्तों और पास-पड़ोस के लोगों ने मुझे बहुत समझाया कि ऐसे मौके बार-बार नहीं मिलते और इन्हें खोना मूर्खता होगी। तुम्हें आगे रिसर्च करना चाहिए। इससे भविष्य और उज्जवल होगा। इसके लिए मुझे लोगों से कई तरह की बातें सुनने को मिलीं, पर मैं अपने फैसले पर अडिग रही। मेरा मानना है कि हमें वही कार्य करना चाहिए, जिससे हमारे मन को सच्ची खुशी मिले। अब मैं अपने कार्य से पूरी तरह संतुष्ट हूं और मुझे अपने उस निर्णय पर जरा भी अफसोस नहीं है। मैं इस बात का पूरा यकीन करती हूं कि हर इंसान को अपने जीवन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण निर्णय खुद ही लेने चाहिए।

ध्यान नहीं दिया व्यर्थ की बातों पर

मैंने शास्त्रीय संगीत में विशारद की उपाधि हासिल की है, पर शादी के बाद घर-गृहस्थी की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गई। मैं जॉब करना चाहती थी, लोगों के सामने स्टेज पर गाना चाहती थी, जब भी मैं अपनी यह इच्छा जाहिर करती तो मेरे मायके-ससुराल वाले साथ मिलकर मुझे समझाने लगते कि ये सब बेकार की बातें हैं, बाहर की दुनिया स्त्रियों के लिए सुरक्षित नहीं है। अगर गाने का इतना ही शौक है तो घर पर ही रियाज कर लिया करो, लेकिन मैं अपनी पहचान बनाना चाहती थी। इसलिए मैंने लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपनी सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए शहर की कुछ सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर मैंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गाना शुरू कर दिया। आज जब लोग मेरे गायन की प्रशंसा करते हैं तो इससे मुझे सच्ची आत्म-संतुष्टि मिलती है। इतना ही नहीं, अब पारिवार के लोग भी मेरी इस कामयाबी पर गर्व करते हैं।

इन सात मंत्रों से रहा जा सकता है खुश

- अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखें। साथ ही प्रतिदिन अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करें। याद रखें, जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है, बस पूरी शक्ति के साथ प्रयास करने की जरूरत है। नकारात्मक सोच रखने से न केवल हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता है, बल्कि हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है।
- पुरानी यादों और बातों को भूलकर वर्तमान पर अपना ध्यान केंद्रित करें। याद रखें यदि आप सिर्फ पुरानी यादों और बातों के बारे में सोचती रहेंगी तो वर्तमान का सुख उठाने से वंचित रह जाएंगी।
- जिस जगह या स्थान में जाने पर आपके मन को सुकून मिलता हो, ऐसी जगह पर बार-बार जाएं, लेकिन जहां जाने पर आपका मन दुखी हो जाता हो, वहां बिल्कुल न जाएं।
- जब भी मौका मिले मनपसंद संगीत सुनें। कई शोध-अध्ययनों से यह बात साबित हो चुकी है कि पसंदीदा संगीत तनाव के स्तर को काफी कम कर देता है।
- न किसी ने सही कहा कि किसी को नाराज करने में एक मिनट का भी समय नहीं लगता, लेकिन किसी को हंसाने में घंटों बीत जाते हैं। इसलिए स्वयं भी हंसें और दूसरों को भी हंसने का अवसर प्रदान करें।
- आप जो खाती हैं वही आपके चेहरे और शरीर से झलकता है। खानपान या रहन-सहन में थोड़ी-सी लापरवाही का असर सीधा आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए अपने खानपान पर पर्याप्त ध्यान दें। मौसमी सब्जियों और फलों का नियमित सेवन करें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आपका खानपान कलरफुल हो अर्थात आपके भोजन में हर रंग का समावेश होना चाहिए।
- विशेषज्ञों का कहना है कि संतुलित डाइट से आप हमेशा फिर रह सकती हैं। न चेहरे पर रौनक तभी आती है, जब आपके शरीर को पूर्ण विश्राम मिले। इसके लिए जरूरी है कि पर्याप्त नींद लें। पर्याप्त नींद लेने से न केवल चेहरे पर चमक आती है, बल्कि स्वास्थ्य भी सही रहता है।

स्ट्रीट शॉपिंग में अच्छी बार्गेनिंग के लिए फॉलो करें ये स्मार्ट ट्रिक्स

स्ट्रीट शॉपिंग में सही बार्गेनिंग करने के लिए आप कुछ आसान ट्रिक्स को फॉलो कर सकती हैं और अच्छे सामान सही दामों में खरीद भी सकती हैं।

दिल्ली की सरोजिनी नगर मार्केट हो या फिर मुंबई की लिंकिंग रोड मार्केट, भला किसे सस्ते दामों में अच्छे सामान की शॉपिंग करना अच्छा नहीं लगता है। यूं कहा जाए कि स्ट्रीट शॉपिंग कई लोगों की जरूरत नहीं बल्कि शौक होता है। दरअसल स्ट्रीट मार्केट ऐसे मार्केट होती है जिसमें कई तरह की अच्छी और ब्रांडेड चीजें भी सही दामों में मिल जाती हैं। जब भी स्ट्रीट शॉपिंग की बात आती है तब आप में से कई लोग दुकानदार के बताए दामों पर ही चीजें खरीद लेते होंगे और कई लोग दाम कम कराने के लिए अच्छी बार्गेनिंग भी करते होंगे। इस तरह की मार्केट में कई बार दुकानदार किसी भी सामान के दाम मनचाहे ढंग से बताते हैं और अगर आपने ठीक तरह से बार्गेनिंग नहीं की तो वो आपको सस्ते दामों वाले सामान भी ज्यादा दामों पर बेच सकते हैं। इसलिए स्ट्रीट शॉपिंग में आपको अच्छी बार्गेनिंग की जरूरत होती है जिससे आप सही सामन उचित दामों में खरीद सकें। अगर आपको बार्गेनिंग नहीं आती है तो आप कुछ स्मार्ट ट्रिक्स से स्ट्रीट शॉपिंग में बार्गेनिंग कर सकते हैं।

कई दुकानों और स्टालों की जांच करें

आप चाहे दिल्ली की सरोजिनी नगर में स्ट्रीट शॉपिंग कर रही हों या गोवा की फ्ली मार्केट में सामान खरीद रही हों, सबसे पहले आपको किसी एक सामान के लिए कई अलग -अलग स्टालों की जांच करनी चाहिए। ऐसा करके आप देखेंगे कि अधिकांश दुकानों और स्टालों में एक ही तरह के कपड़े और सामान हो सकते हैं। कई बार किसी कपड़े का पैटर्न, प्रिंट, कलर सब लगभग एक जैसा ही होता है लेकिन उनके दाम अलग होते हैं ऐसे में अगर आपको कोई ऐसी चीज मिलती है जो आपको पसंद है, तो कई दुकानों से उसके दाम पता करें। इससे आपको यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि क्या कोई दुकानदार कीमत को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। सामान्य तौर पर मार्केट की छोटी दुकानों की तुलना में सड़क के किनारे के स्टालों की दरें हमेशा सस्ती होंगी आप सही कीमत के हिसाब से बार्गेनिंग करके शॉपिंग करें।

थोड़ा झूठ भी है जरूरी

स्ट्रीट शॉपिंग के समय आपके लिए थोड़ा झूठ बोलना भी अच्छा होता है। यदि आप चाहते हैं कि दुकानदार आपको गंभीरता से ले, तो आपको यह दिखाना होगा कि आप अलग-अलग जगह और कीमतों से परिचित हैं। आप स्ट्रीट शॉपिंग दुकानदार से यह कह सकते हैं कि आप उस खास जगह और बाजारों में अच्छी तरह से खरीदारी करते हैं और आप हर एक सामान के सही दामों से परिचित हैं। ये स्मार्ट ये न जटाएं कि आपको किसी सामान की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर दुकानदार आपकी जरूरत को समझ जाता है तो वो बढ़ चढ़ कर दाम बताता है। इसलिए आपका न्यूट्रल रिएक्शन बार्गेनिंग में मदद कर सकता है।

दुकानदार की कीमत का आधा दाम बताएं

कुछ मामलों में यह बेतुका लग सकता है, लेकिन हमेशा जब भी आओ स्ट्रीट शॉपिंग कर रहे हों तब आप दुकानदार द्वारा बताए दाम का लगभग 50-60% कम करने से आप उस कीमत के करीब पहुंच जाते हैं, जो वास्तव में उस सामान की कीमत है। दरअसल स्ट्रीट शॉपिंग में दुकानदार अपनी इच्छा से दाम बढ़ा देते हैं जो बार्गेनिंग से कम किये जा सकते हैं।

चीजों में ढूढें डिफेक्ट

जब आप स्ट्रीट शॉपिंग के लिए जाएं तो किसी भी सामान में कोई ऐसा डिफेक्ट ढूंढने की कोशिश करें जो वास्तव में डिफेक्ट न होकर उस कपड़े का डिजाइन या कलर ही हो। लेकिन आप डिफेक्ट के नाम पर अच्छी बार्गेनिंग करके स्ट्रीट शॉपिंग (भारत के इन राज्यों में उठाएं स्ट्रीट मार्केट का मजा) में चीजों के दाम कम करा सकती हैं। स्ट्रीट मार्केट में मिलने वाले बहुत से कपड़े वास्तव में ऐसे होते हैं जो होल सेल से आते हैं और इसमें कोई बहुत छोटा सा डिफेक्ट भी हो सकता है जैसे बटन का ढीला होना या किसी जगह की सिलाई खुलना। सामान सेलेक्ट करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप उसके हर इंच को स्कैन कर लें। यदि डिफेक्ट ज्यादा बड़ा नहीं है तो आप इसके दाम कम करा सकते हैं। वास्तव में यह एक स्मार्ट बार्गेनिंग ट्रिक है।

मेहंदी का रंग चढ़ेगा गहरा जानिए आसान तरीके

महिलाएं 16 श्रंगार करती है, सजती - संवरती है। उन्हीं में से मेहंदी भी श्रंगार का ही हिस्सा है। इसके बिना तीज त्योहार या किसी भी प्रकार का पर्व पूरा नहीं होता है। लेकिन बदलते दौर में मेहंदी के रंग भी फीके पड़ने लगे हैं। कुछ नुस्खें है जिन्हें फॉलो कर आप अपनी मेहंदी का रंग गहरा कर सकती हो। तो आइए जानते हैं 5 आसान से टिप्स -

- मेहंदी को घोलते समय उसमे में सादा पानी नहीं मिलाते हुए चाय की पत्ती का पानी डालें। इसे बनाने के लिए तपेली में एक कप पानी रखें,उसमे पत्ती डाल दें। पानी को थोड़ी देर उबाल लें और ठंडा होने के बाद उससे मेहंदी घोल लें।
- मेहंदी घोलने से पहले मेहंदी में ही तेल डाल दें। इससे मेहंदी का कलर एक जैसा आता है। वहीं मेहंदी हल्की सी सुख जाने के बाद एक कटोरी में पानी लेकर उसमें शक्कर डाल दें। इसके बाद रूई की मदद से मेहंदी पर लगाएं। कलर अच्छा आएगा।
- मेहंदी सूखने के बाद आप रूई की मदद से अचार का तेल भी लगा सकते हैं। इससे मेहंदी का कलर खूब जमेगा।
- मेहंदी सूखने के बाद आप इसे हटा देते हैं, और लेकिन पानी से हाथ नहीं धोएं। इसके पहले थोड़ी देर के लिए घरेलू बाम का इस्तेमाल करें। अपने हाथों पर हल्के हाथों से लगा लें। ध्यान रहे उंगलियों के पोरस पर नहीं लगाएं। ताकि गलती से आंख में नहीं लग जाएं।
- मेहंदी सूखने के बाद रूई की मदद से हल्के हाथों से मेहंदी का तेल लगा लें। इसके बाद करीब 3 घंटे तक हाथों पर पानी नहीं लगाएं। फिर देखिए कितना गहरा रंग आता है।

कैसा होना चाहिए बच्चे का पूरे हफ्ते का डाइट चार्ट

सही डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बच्चे को अच्छी डाइट की जरूरत होती है। अगर आप बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से खाना खिलाएं, तो इससे उसके विकास में काफी मदद मिलती है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि ढाई साल के बच्चे का हफ्तेभर का डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए।

सोमवार का भोजन चार्ट

ढाई साल के बच्चे को सुबह 7 से 8 बजे एक कप दूध में ड्राई फ्रूट्स के साथ एक चम्मच गुड़ और शहद डालकर दें। इसके बाद नाश्ते में 830 से 930 बजे के बीच बच्चे को नारियल की चटनी के साथ एक डोसा खिलाएं। इसके कुछ देर बाद 11 से 1130 बजे बच्चे को चुकंदर और गाजर का एक कप सूप पिलाएं। 1 से 2 बजे के बीच बच्चे का लंच करवाना है जिसमें उसे आधा कप हरी मटर के चावल और आधा कप चिकन करी खिलानी है। वेजिटेरियन हैं तो आधा कप चावल, आधा कप सहजन की दाल में एक चम्मच घी डालकर और आधा कप दही दें। शाम को 430 से 530 बजे बच्चे को पनीर सैंडविच दें और फिर रात को 730 से 8.15 बजे डिनर में एक मटर का परांठा और आधा कप दही खिलाएं।

मंगलवार की डाइट

सुबह बच्चे को एक कप दूध में बादाम और एक चम्मच गुड़ और शहद डालकर दें। नाश्ते में बच्चे को सेरेलेक खिला सकती हैं। इसके थोड़ी देर बाद एक वेज रोज और आधा कप तरबूज खिलाना है। लंच में आधा कप वेज पुलाव और आधा कप रायता खिलाएं। शाम को एक कप मैंगो जूस पिलाएं। अब डिनर में बच्चे को घी लगाकर एक रोटी और आधा कप चुकंदर की सब्जी दें। रात को सोने से पहले एक कप दूध में एक चम्मच गुड़ या शहद डालकर दें।

बुधवार का खाना

25 साल के बच्चे को सुबह ड्राई फ्रूट्स के साथ एक कप दूध दें। ब्रेकफास्ट में एक इडली और दो चम्मच नारियल की चटनी खिलाएं। कुछ देर बाद एक कप संतरे का जूस पिलाना है। लंच में आधा कप चावल, आधा कप दाल पालक, एक चम्मच घी और आधा कप दही खिलानी है। इसके थोड़ी देर बाद एक रागी का लड्डू और एक केला खिलाएं। डिनर में बच्चे को आधा कप वेजिटेबल खिचड़ी के साथ आधा कप दही दें। रात को सोने से पहले एक कप दूध में एक चम्मच गुड़ या शहद डालकर दें।

बृहस्पतिवार का भोजन चार्ट

सुबह उठने के बाद बच्चे को एक कप केले के मिल्क शेक में एक चम्मच शहद डालकर दें। इसके बाद नाश्ते में एक कटोरी सेरेलेक खिलाएं। कुछ देर बाद बच्चे को आधा कप मिक्स वेज सूप और आधा कप अनानास खिलाना है। दोपहर को लंच में आधा कप मिक्स वेजिटेबल राइस और आधा कप दाल फ्राई खिलाएं। लंच के बाद एक बेसन का लड्डू और आधा कप खरबूजा खिलाएं। डिनर में आधा कप वेज नूडल्स दें। रात को सोने से पहले एक कप दूध में एक चम्मच गुड़ या शहद डालकर दें।

शुक्रवार का डाइट चार्ट

शुक्रवार को सुबह नाश्ते से पहले ड्राई फ्रूट्स के साथ एक कप दूध दें। ब्रेकफास्ट में एक कप पोहा खिलाएं। फिर थोड़ी देर बाद एक संतरा देना है। बच्चे को लंच में आधा कप चावल, आधा कप लौकी की दाल और एक चम्मच घी डालकर खिलाएं। शाम को एक वेज कटलेट के साथ आधा कप लस्सी पिलाएं। रात को डिनर में एक परांठा और आधा कप दाल फ्राई में एक चम्मच घी डालकर परोसें। रात को सोने से पहले एक कप दूध में एक चम्मच गुड़ या शहद डालकर दें।

शनिवार का खाना कैसा रखें

सुबह नाश्ते से पहले ड्राई फ्रूट्स के साथ एक कप दूध दें। इसके बाद नाश्ते में एक कटोरी सेरेलेक खिलाएं। थोड़ी देर बाद एक कप पपीता और 4 से 5 खजूर खिलाएं। लंच में बच्चे को घी लगाकर एक रोटी और आधा कप गाजर और आलू की सब्जी दें। शाम को एक कप गाजर का सूप पिलाएं। रात को डिनर में आधा कप वेजिटेबल पास्ता खिलाएं। रात को सोने से पहले एक कप दूध में एक चम्मच गुड़ या शहद डालकर दें।